बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 227

शिक्षा के लिए धन

उच्च शिक्षा की फंडिंग में सरकारी धन के उपयोग को लेकर बहस नई नहीं है। उच्च शिक्षा के अधिकांश लाभ जहां इसे हासिल करने वाले व्यक्ति को होते हैं, वहीं इसके कुछ बाहरी लाभ भी हैं, मसलन प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ, उच्च शोध एवं नवाचार और अर्थव्यवस्था में अधिक कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता। उच्च शिक्षा में शामिल लागत को देखते हुए खासकर स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) पाठ्यक्रमों की तो छात्रों को अक्सर अधिक राशि चुकानी होती है। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अपने दायरे में लेने वाली इस वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत उन प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋण प्रदान किया जाएगा जिन्हें उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला मिला हो लेकिन वे वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। शुरुआत में यह योजना देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगी।

सेंट्रल सेक्टर ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) और शैक्षणिक ऋण के लिए ऋण गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) के पूरक के रूप में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना स्थगन अवधि के दौरान 4.5 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को पूर्ण ब्याज अनुदान प्रदान करेगी। इसके अलावा 8 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को बकाया देनदारी पर 75 फीसदी की ऋण गारंटी मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करेगा।

देश में शिक्षा ऋण का बाजार बीते कुछ वर्षों में काफी विकसित हुआ है। शिक्षा ऋण के तहत बकाया पोर्टफोलियो 2022-23 में 17 फीसदी बढ़कर 96,847 करोड़ रुपये हो गया। बहरहाल देश के शिक्षा ऋण का 90 फीसदी से अधिक हिस्सा विदेशों में पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वितरित कुल शिक्षा ऋण का करीब 8 फीसदी फंसे हुए कर्ज में तब्दील हो गया। यह बैंकिंग क्षेत्र के औसत फंसे हुए कर्ज से अधिक है। औसत डिफॉल्ट दर भी प्रमुख संस्थानों के छात्रों के शिक्षा ऋण की डिफॉल्ट दर से बहुत अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि शिक्षा ऋण के क्षेत्र में ऐसे छात्रों का योगदान अधिक है जो दूसरे दर्जे के संस्थानों में पढ़ते हैं। इस संदर्भ में योजना न केवल गरीब विद्यार्थियों को ऋण तक आसान पहुंच मुहैया कराएगी बल्कि कुछ हद तक बैंकों को भी बचाएगी।

बहरहाल, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आसान ऋण की मदद से उच्च शिक्षा को सब्सिडी देना जरूरी हो सकता है लेकिन यह वांछित परिणाम पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। देश में समस्या न केवल ऋण के किफायती होने या वित्तीय मदद के विकल्पों की है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की उपलब्धता भी एक अहम मुद्दा है। राष्ट्रीय पात्रता सह अर्हता परीक्षा समेत शीर्ष परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक होने, कोचिंग सेंटरों का विस्तार और शीर्ष संस्थानों में प्रवेश की तैयारी कर रहे बच्चों द्वारा आत्महत्या करने जैसी घटनाएं अच्छे उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी की एक बड़ी समस्या का संकेत हैं। इस वजह से अधिकांश शैक्षणिक ऋण विदेशों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे में जहां उच्च शिक्षा के ऋण की उपलब्धता में सुधार का स्वागत किया जाना चाहिए, वहीं सरकार को अधिक गहरी समस्या पर भी नजर रखनी चाहिए। भारत को अगर तेजी से बदलती दुनिया में अगली पीढ़ी को प्रासंगिक रखना है तो उसे बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान तैयार करने होंगे।

मध्य आय का जाल और भारत का हाल

भारत को विकसित देश बनना है और दूसरों के लिए बेहतर राह निर्धारित करनी है तो उसे पांच अहम सुधार करने होंगे। बता रहे हैं अजय छिब्बर

विश्व बैंक की हालिया विश्व विकास रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 108 देश इस समय मध्य आय के जाल में फंसे हुए हैं। उसके मुताबिक ये वे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) 2024 में 1,146 डॉलर से 14,005 डॉलर के बीच है। इससे कम आय वाले देशों को निम्न आय और अधिक आय वाले देशों को उच्च आय वाले देशों में गिना जाता है। उसने मध्य आय की श्रेणी (एमआईसी) को दो उपश्रेणियों में बांटा है। 1,146 डॉलर से 4,515 डॉलर आय वाले देशों को निम्न मध्य आय (एलएमआईसी) और इससे अधिक आय वालों को उच्च मध्य आय (यूएमआईसी) की श्रेणी में रखा गया है। मध्य आय समूह में शामिल देशों की संख्या 2000 में 90 थी जो 2010 में 109 हो गई और आज 108 है। ये जाल में फंसे नजर आते हैं लेकिन यह बात भ्रामक है।

आय के इस सोपान में हमें विभिन्न देश ऊपर चढ़ते दिखते हैं। उच्च आय वाले देशों की संख्या 2000 के 51 से बढ़कर 2023 में 85 हो गई, जबकि निम्न आय वाले देशों की संख्या 2000 के 63 से कम होकर 2023 में 26 रह गई। यह जाल नहीं बल्कि विकास की सीढ़ी पर कठिन चढ़ाई है। पूर्वी और दक्षिणी यूरोप के कई देशों को यूरोपीय संघ की सदस्यता से मदद मिली है और वे सीढ़ी पर ऊपर बढ़े हैं। दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर जैसे कई पूर्वी एशियाई देश भी आगे बढ़ने में सफल रहे हैं। चीन और मलेशिया जैसे देश भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। वियतनाम अभी दूर है और वह निम्न मध्य आय वाले देशों में है मगर उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। लैटिन अमेरिका में चिली और उरुग्वे उच्च आय का दर्जा पाने में कामयाब रहे हैं मगर ब्राजील, मेक्सिको, पेरू और कोलंबिया जैसे कई देश फंसे हुए नजर आते हैं। किसी समय उच्च आय वाले समूह में रहे अर्जेंटीना और वेनेजुएला जैसे देश अब मध्य आय वाले देशों में फंसे दिख रहे हैं। तेल और खनिज संपदा वाले कुछ देश भी इसमें कामयाब हुए हैं लेकिन इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया और नाइजीरिया जैसे कई देश जूझते नजर आ रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) आय के स्तर के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर भी आकलन करता है। उसमें भी विकास के मार्ग पर प्रगति नजर आती है। उसने एचडीआई में मिले अंको के आधार पर मानव विकास की चार श्रेणियां तैयार की हैं:

निम्न (0.55 से कम), मध्यम (0.55 से 0.7), उच्च (0.7 से 0.8) और अति उच्च (0.8 से अधिक)। 1990 में 160 में से 70 देश निम्न मानव विकास वाले थे मगर 2022 में 185 देशों में से केवल 26 देश इस श्रेणी में रह गए। अति उच्च मानव विकास वाली श्रेणी के देश 1990 में केवल 47 थे, जिनकी संख्या 2022 में बढ़कर 69 हो गई। उच्च मानव विकास वाले देश 1990 में 18 ही थे, जो 2022 में बढ़कर 49 हो गए। यह सुधार केवल आय में नहीं हुआ बल्कि यह व्यापक सूचकांक है। इससे पता चलता है कि इन श्रेणियों में व्यापक गतिशीलता नजर आती है जहां देश निम्न से मध्य और उच्च तथा आखिर में अत्यधिक उच्चतम मानव विकास की श्रेणी में जा रहे हैं। ऐसे में मध्य आय से गुजरना जाल में फंसना नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर सफर में पड़ाव लगता है। मजबूत संस्थाओं वाले, लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाले देश या तेल जैसे संसाधन वाले अथवा यूरोपीय संघ की सदस्यता से लाभान्वित होने वाले देश तेजी से आगे आते हैं।

भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ पहले ही अटकल लगा रहे हैं कि निम्न मध्य आय श्रेणी में आने वाला भारत मध्य आय के जाल में फंसेगा या नहीं। विश्व बैंक भी कह चुका है कि 2,540 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ (अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की केवल 3 फीसदी) भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के चौथाई हिस्से तक पहुंचने में ही 75 वर्ष लग जाएंगे।

हालांकि यह सही पैमाना नहीं है। विश्व बैंक के नए प्रेसिडेंट अजय बंगा ने संस्था के मिशन को बदलकर उचित लक्ष्य रख दिया है, 'रहने योग्य ग्रह पर गरीबी का उन्मूलन।' मगर हर किसी ने अमेरिकी जीवनशैली अपनाई तो धरती रहने योग्य नहीं रह जाएगी। इसके बजाय यूएनडीपी के अनुसार हमें रहने के लिए नौ ग्रहों की जरूरत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत यूं भी पृथ्वी के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि वह जलवायु समझौतों से बाहर निकल जाएंगे और जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। यहां तक कि चीन भी अमेरिका की नकल कर रहा है और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के पहले ही दुनिया में कार्बन डाई ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए?

इसका रास्ता विकास मापते समय पारिस्थितिकी को हो रहे नुकसान का पता लगाने से मिल सकता है। सतत विकास सूचकांक गैर टिकाऊ विकास को मापता है, जिसके लिए वह मानव विकास सूचकांक का पारिस्थितिकी सूचकांक से भाग करता है। पारिस्थितिकी सूचकांक प्रति व्यक्ति कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन और निर्माण में ऐसी सामग्री के इस्तेमाल से बनता है, जो सामग्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाती है। इसे पैमाना बनाएं तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर का विकास स्कोर बहुत कम हो जाता है। एसडीआई का उच्चतम स्तर 14,000 डॉलर प्रति व्यक्ति जीएनआई और 0.8 एचडीआई अंक के बराबर है, जिसे भारत 2047 तक हासिल कर सकता है। इस दौरान उसका कार्बन उत्सजर्न भी पहले वहां पहुंच चुके देशों की तुलना में कम होगा।

इन लक्ष्यों के साथ भारत का विकसित देश बनना असंभव नहीं है। इसे हासिल करने के लिए उसे पांच अहम सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि उच्च मध्य आय वर्ग में पहुंचने पर उसके पास निरंतर आगे बढ़ने के लिए जरूरी तंत्र मौजूद हो।

ये सुधार हैं- प्रशासन, लोक वित्त और विकेंद्रीकरण की बेहतर संस्थाएं, उच्च गुणवत्ता वाली व्यापक शिक्षा, स्त्री-पुरुष भेद में कमी, आयात संरक्षण और औद्योगिक नीति ही नहीं उत्पादन के कारकों में भी सुधार के साथ नवाचार तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर जोर बढ़ाना एवं कोयले पर निर्भरता तेजी से घटाना। यह चुनौती भरा है, लेकिन ऐसा करके देश की 1.5 अरब आबादी का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसा करते हुए भारत न केवल विकसित देश बन जाएगा बल्कि वह दूसरों को भी विकास पथ पर चलने का बेहतर रास्ता दिखाएगा।

(लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी के प्रतिष्ठित विजिटिंग स्कॉलर हैं)

विश्व बैंक देश वर्गीकरण

	1990	2000	2010	2023
उच्च आय	38	51	70	85
उच्च मध्यम	29	37	53	54
निम्न मध्यम	56	53	56	51
कम आय	51	63	35	26
वर्गीकृत नही	43	13	3	1
कुल	214	214	217	217

यूएनडीपी मानव विकास (एचडी) वर्गीकरण

	1990	2000	2010	2022
अति उच्च एचडी	47	53	47	69
उच्च एचडी	18	53	46	49
मध्यम एचडी	25	23	46	41
कम एचडी	70	44	37	26
कुल	160	173	176	185

सतत विकास सूचकांक (एसडीआई) और आय

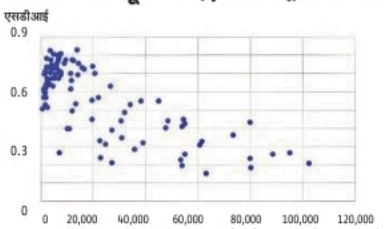

एसडीआई और एचडीआई

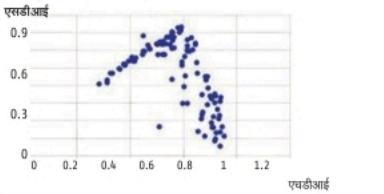

पड़ोसी देशों पर बरकरार है भारत का असर

साल खत्म हो रहा है और अमेरिका में नई सरकार शासन संभालने जा रही है। दुनिया बदल रही है। ऐसे में भारत के लिए दक्षिण एशिया में क्या संभावनाएं हैं?

कई लोगों का कहना है कि भारत ने साल भर अपने पड़ोस में दोस्तों को दुश्मन बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। वे भूटान की ओर इशारा करते हैं, जहां यह मांग जोर पकड़ रही है कि हर चीज के लिए भारत पर ही निर्भर नहीं रहा जाए। नेपाल में नई सरकार बन चुकी है और माना जा रहा है कि वह भारत के बिल्कुल खिलाफ है। नेपाल के पर्यवेक्षकों का कहना है कि भारत से न्योता 'नहीं मिलने पर' नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दिसंबर के अंत में चीन जाएंगे और उसके बाद भारत आएंगे। ऐसा हुआ तो पुरानी परंपरा टूट जाएगी। सत्तापलट की शिकार हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय बांग्लादेश की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जा रही हैं। उन्हें शरण देकर भारत ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तान के साथ गतिरोध इतना बढ़ चुका है कि अनुभवी राजनयिक भी पूछ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में दोबारा कभी दोस्ती हो भी पाएगी या नहीं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके घोषित रूप से भारत विरोधी हैं और वैचारिक रूप से चीन के करीब हैं। इसलिए उस मोर्चे पर भी हमें कुछ हासिल होता नहीं दिखता। 'इंडिया आउट' अभियान के साथ भारत ने मालदीव में मैत्रीपूर्ण स्वीकार्यता पूरी तरह खो दी है। दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीति में गड़बड़ी है और चीन का दबदबा है। सरसरी तौर पर देखने पर लगता है कि भारत फंसा हुआ है लेकिन क्या वाकई हालात इतने खराब हैं?

इस वर्ष अक्टूबर में भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने 40 मेगावॉट बिजली के व्यापार के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल पहली बार किसी अन्य देश को बिजली बेच रहा है क्योंकि अभी तक भारत ही खरीदार रहा है। अब नेपाल भारत को बिजली भेजगा और भारत उतनी ही बिजली बांग्लादेश को भेजेगा। यह पहला मौका है, जब भारत ईमानदारी से बिचौलिये की भूमिका निभाएगा। यह 1997 से बहुत अलग है, जब भारत और नेपाल के बीच बिजली व्यापार समझौता वहां की संसद में पेश तक नहीं हो सका था क्योंकि उसे भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा था। नेपाल का संविधान कहता है कि नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित विदेशी समझौतों को संसद द्वारा दो तिहाई बहुमत से मंजूर करना होगा और उस समय भारत पर शंकाओं का बाजार गर्म था। केवल 40 मेगावॉट की इजाजत मिली, लेकिन शुरुआत तो हुई। श्रीलंका में जब इस साल सितंबर में दिसानायके राष्ट्रपति चुने गए थे तब नीतियों में आमूल-चूल बदलाव होने के गंभीर अनुमान जताए गए थे। उनका और उनकी पार्टी का अतीत मार्क्सवाद, लेनिनवाद, त्रॉत्सकीवाद से जुड़ा रहा है और बाद में उसका संबंध अति राष्ट्रवादी सिंहल बौद्ध विचारधारा से भी रहा है। इसी वजह से भारत-श्रीलंका रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ने के अनुमान लगाए जा रहे थे। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। यह सच है कि सरकारी विमानन कंपनी श्रीलंकन एयरवेज का निजीकरण टाल दिया गया है और सरकारी सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी निजीकरण के बजाय सुधारों पर जोर दिया जाएगा। परंतु अदाणी-जॉन कील्स होल्डिंग्स (जेकेएच) के संयुक्त उपक्रम वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का पहला चरण 2024-25 की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा। लाल सागर में बाधा उत्पन्न होने के कारण कोलंबो के रास्ते काफी कारोबार हो रहा है और अच्छी कमाई हो रही है। वहां की सरकार इस कंटेनर टर्मिनल का राष्ट्रीयकरण करने भी नहीं जा रही है। मालदीव में शोर-शराबे को ताक पर रखकर कूटनीति अपना काम कर रही है। मालदीव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के कारण वहां इंडिया आउट का नारा बुलंद हुआ था लेकिन अक्टूबर में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की भारत यात्रा के बाद वह व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर सहमत हो गया है, जिसमें रक्षा क्षेत्र भी शामिल है। अक्टूबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान गए, जो पिछले 12 साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांगों के बावजूद बांग्लादेश की नई सरकार यह स्वीकार करती दिख रही है कि वहां के लोगों की दुश्मनी शेख हसीना से है भारत से नहीं। करीब 50 फीसदी बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद बांग्लादेश ने अदाणी पॉवर का बकाया चुका दिया है। कंपनी अपने झारखंड संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली देती है। इस तरह बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि वह राजनीति को व्यापार के रास्ते में नहीं आने देगा। ऊपर बताया गया त्रिपक्षीय बिजली समझौता चल ही रहा है।

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

यकीनन दक्षिण एशिया में चीन की अनदेखी मुश्किल है। परंतु पड़ोस में उसे रोकने की रणनीति पर काम चल रहा है, जो ऐप्लिकेशंस पर प्रतिबंध से भी आगे जाती है। भारत ने नेपाल से कहा है कि वह उन सरकारी या निजी कंपनियों से बिजली नहीं खरीदेगा, जिनमें चीन का निवेश है। नेपाल के निवेशकों ने चीन की कंपनियों को टालना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश तो शेख हसीना के कार्यकाल में भी चीन का शत्रु नहीं था लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में उसका रुख क्या होगा। भूटान के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री शेरिंग तोपगे ने चुनावों के बाद इस वर्ष के आरंभ में अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए भारत को ही चुना, जबकि देश के राजनीतिक कुलीनों का विचार था कि देश को अपनी भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। असम-भूटान सीमा पर भारत नया शहर 'गेलेफू' बनाने में मदद कर रहा है, जिसे भविष्य का शहर कहा जा रहा है। बयानबाजी से कुछ भी लगे मगर हकीकत यही है कि पड़ोस में अभी तक भारत का असर भी है और दोस्त भी हैं।

आपका पक्ष

भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत

भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर स्पष्ट स्थिति नहीं है और एलएसी या वास्तविक नियंत्रण रेखा को ही सीमा माना जाता है। लेकिन इस एलएसी को लेकर भी भारत और चीन के अपने-अपने दावे हैं। इस कारण से भी दोनों देश के सैनिक कई बार एलएसी पर टकराव की मुद्रा में आ जाते हैं। भारत और चीन के बीच हुए इस ताजा समझौते में देपसांग और डेमचोक में गश्त का मुद्दा शामिल है। इस समझौते के बाद देपसांग और डेमचोक से दोनों देश की सेनाओं को पीछे हटना होगा। अगर एलएसी पर भारत और चीन गलवान से पहले अर्थात अप्रैल 2020 की स्थिति में आ जाते हैं, तो यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत होगी। गौरतलब है कि अगस्त 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में टकराव हुआ था। हालांकि, पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव घटाने और सैनिकों की तैनाती रोकने के लिए दोनों ओर से कोई चर्चा नहीं हुई है, जबकि 2020 के अप्रैल महीने से पहले की स्थिति बहाल करने के लिए यह जरूरी था। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों के सभी अधिकार बहाल नहीं किए गए हैं, क्योंकि गलवान, गोगरा, पैंगॉन्ग के नॉर्थ ब्लॉक और कैलाश रेंज में बफर जोन की स्थित वैसी ही बनी हुई है। इस बारे में भी किसी ठोस समझौते की दरकार है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

भारत और चीन के बीच शांति समझौते के बाद देपसांग और डेमचोक में सैनिकों की गश्त शुरू हो सकी

प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए जागे सरकार

अगर देश में कोई भी खाने की चीज वह भी गरीब से गरीब के लिए भी रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली हो, महंगी हो जाए तो सरकार को उसकी कीमत कम करने के उपाय प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। देश में विकास के वादे और दावे तब तक खोखले माने जा सकते हैं, जब तक देश में पैदा होने वाली चीजें महंगी हो। अब तो सरकार को प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ राज्यों में इसकी कीमतें 100 रुपये से अधिक होने की खबरें आने लगी हैं। अगर सरकार प्याज की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए प्रयास नहीं किए तो भविष्य में महंगा प्याज सत्ताधारी दल पर चुनावों के समय बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए सरकार को प्याज की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए प्रयास करने चाहिए और जो प्याज भारत से निर्यात हो रहा है तो उस पर रोक लगाकर देश की आम जनता को कम दाम पर प्याज उपलब्ध कराना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों को चाहिए कि वे ऐसी तकनीक विकसित करें कि देश के हर राज्य में प्याज की पैदावार बढ़े और पूरा देश नासिक में प्याज की पैदावार पर ही निर्भर नहीं रहे। प्राकृतिक कारकों से फसलों को बरबाद होने से बचाने के लिए भी गंभीरता दिखानी होगी। इसके साथ ही फल सब्जियों के दाम में भी कमी लाने की आवश्यकता है। सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। बाजार में कोई भी सब्जी 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच बिक रही है। कुछेक सब्जी 50 से 60 रुपये के बीच है। अगर प्याज व सब्जियों के बढ़ते दाम के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं तो उनमें समय रहते सुधार करने की आवश्यकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को सिंगापुर के राष्ट्रपति तर्मण षणमुगरत्नम (दाएं) से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग सहित सिंगापुर के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर दृष्टिकोण साझा किया। जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पूरी कर सिंगापुर पहुंचे हैं।

1,78,276 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन्स, देशभर में 279 सबस्टेशन और 5,37,276 एमवीए की ट्रांसफार्मेशन की क्षमता है।

एनबीसीसी का भारतीय मानक ब्यूरो से समझौता

नई दिल्ली (वि)। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) को देश के पांच प्रमुख स्थानों पर नए कार्यालय स्थलों, प्रयोगशालाओं और अन्य अवसंरचना के विकास के लिए बीआईएस द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य सौंपा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में संजय पंत, उप महानिदेशक, बीआईएस और एसके पांडे, मुख्य महाप्रबंधक (इंजी.), एनबीसीसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं), एनबीसीसी तथा एनबीसीसी और बीआईएस. के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। परियोजना की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये से अधिक है।

मौका चूकें नहीं
10 नवम्बर से पहले करें अप्लाई
अधिक जानकारी के लिए
संपर्क करें - 1800 116 090 (टोल फ्री) या
विजिट करें - pminternship.mca.gov.in या
स्कैन करें

लोगों द्वारा तुम्हारे ऊपर जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनका उपयोग एक सुंदर स्मारक बनाने में करो। -रतन टाटा

चिंता और संकेत

वैश्विक रिसर्च कंपनी इप्सोस की हालिया रिपोर्ट का यह कहना उत्साहित करने वाला है कि दुनिया के 29 देशों में भारत अव्वल है, जहां मौजूदा आर्थिक हालात को सबसे ज्यादा लोग बेहतर मानते हैं। यही नहीं, भारत उन देशों की सूची में सिंगापुर के बाद दूसरी पायदान पर है, जहां के लोगों को लगता है कि उनका देश सही दिशा में जा रहा है। यह स्थिति नागरिकों के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाने के साथ ही देश के विकास की दिशा के बारे में भी एक सकारात्मक संकेत है। दरअसल, महामारी के दौर से दुनिया उबर ही रही थी कि रूस-यूक्रेन और इस्राइल-फलस्तीन युद्धों ने पूरे वैश्विक परिदृश्य को बदल दिया। हूती विद्रोहियों के लाल सागर में व्यापार मार्गों पर निरंतर हमलों की वजह से वैश्विक आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई, तो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाने लगीं। इन स्थितियों के बावजूद अगर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राष्ट्र बना हुआ है, तो इसका बड़ा कारण उसकी आर्थिक नीतियां और मजबूत घरेलू बाजार ही हैं। बेशक विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन और तमाम वैश्विक रेटिंग एजेंसियां भारत की विकास दर की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन इप्सोस की रिपोर्ट एक सतर्क संकेत देती है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसी आर्थिक चुनौतियां अब भी सरकार और नीति निर्माताओं के लिए गंभीर मुद्दे बने हुए हैं। और, यह सिर्फ भारत की बात नहीं है। कुल 29 में से 19 देशों के लोगों के लिए जीवन-यापन लागत में वृद्धि के चलते महंगाई सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। मार्च, 2022 के बाद पिछले महीने पहली बार देखा गया कि दुनिया के लिए महंगाई सबसे बड़ी चिंता नहीं रह गई है, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है। पूरी दुनिया में बेरोजगारी को प्रमुख समस्या मानने वालों की संख्या भले ही कुछ घटी हो, लेकिन पिछली रिपोर्ट की तुलना में अब भारत में रोजगार बाजार के बारे में चिंताएं बढ़ी हैं और इसके साथ ही यह महंगाई के बाद अब देश की दूसरी सबसे बड़ी चिंता बन गई है।

राहत की बात है कि 29 देशों के लोगों में जलवायु को चिंता का विषय मानने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो वाकई गर्म होती पृथ्वी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। भारत के संदर्भ में सबसे अच्छी बात है कि लोगों का अपनी अर्थव्यवस्था पर भरोसा कायम है, जिसका फायदा उठाकर नीतिगत सुधारों व संरचनात्मक विकास की गति को बरकरार रखना जरूरी होगा।

कोई सपना ऐसा नहीं, जो पूरा न हो सके

रतन टाटा के निधन को आज एक महीना हो रहा है। लेकिन वह उन जिंदगियों और सपनों में हमेशा जीवित रहेंगे, जिन्हें उन्होंने सहारा दिया। भारत को एक बेहतर, सहृदय और उम्मीदों से भरी भूमि बनाने के लिए आने वाली पीढ़ियां उनकी सदैव आभारी रहेंगी।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

आज रतन टाटा जी के निधन को एक महीना हो रहा है। पिछले महीने आज के ही दिन जब मुझे उनके गुजरने की खबर मिली, तो मैं उस समय आसियान समिट के लिए निकलने की तैयारी में था। रतन टाटा जी के हमसे दूर चले जाने की वेदना अब भी मन में है। इस पीड़ा को भुला पाना आसान नहीं है। रतन टाटा जी के तौर पर भारत ने अपना एक महान सपूत...एक अमूल्य रत्न खो दिया है।

आज भी शहरों, कस्बों से लेकर गांवों तक, लोग उनकी कमी को गहराई से महसूस कर रहे हैं। यह हम सबका दुख साझा है। चाहे कोई उद्योगपति हो, उभरता उद्यमी हो या कोई प्रोफेशनल हो, हर किसी को उनके निधन से दुख हुआ है। पर्यावरण रक्षा से जुड़े लोग, समाज सेवा से जुड़े लोग भी उनके निधन से उतने ही दुखी हैं। और यह दुख हम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में महसूस कर रहे हैं। युवाओं के लिए वह प्रेरणास्रोत थे। उनका जीवन और व्यक्तित्व हमें याद दिलाता है कि कोई सपना ऐसा नहीं, जिसे पूरा न किया जा सके। उन्होंने सिखाया कि विनम्र स्वभाव के साथ, दूसरों की मदद करते हुए भी सफलता पाई जा सकती है।

रतन टाटा जी भारतीय उद्यमशीलता की बेहतरीन परंपराओं के प्रतीक थे। वह विश्वसनीयता, उत्कृष्टता और बेहतरीन सेवा जैसे मूल्यों के प्रतिनिधि थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया भर में सम्मान, ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रतीक बनकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। फिर भी उन्होंने अपनी उपलब्धियों को पूरी विनम्रता और सहजता के साथ स्वीकार किया।

दूसरों के सपनों का खुलकर समर्थन और सहयोग करना, यह उनके सबसे शानदार गुणों में से एक था। हाल के वर्षों में, वह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मार्गदर्शन करने और भविष्य की संभावनाओं से भरे उद्यमों में निवेश करने के लिए जाने गए। उन्होंने युवा आंत्रप्रेन्योर की आशाओं और आकांक्षाओं को समझा, साथ ही भारत के भविष्य को आकार देने की उनकी क्षमता को पहचाना। भारत के युवाओं के प्रयासों का समर्थन करके उन्होंने नए सपने देखने वाली नई पीढ़ी को जोखिम लेने और सीमाओं से परे जाने का हौसला दिया। उनके इस कदम ने भारत में इनोवेशन और आंत्रप्रेन्योरशिप की संस्कृति विकसित करने में बड़ी मदद की है। आने वाले दशकों में हम भारत पर इसका सकारात्मक असर जरूर देखेंगे।

रतन टाटा जी ने हमेशा बेहतरीन क्वालिटी के उत्पाद और सेवा पर जोर दिया और भारतीय उद्यमों को ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करने का रास्ता दिखाया। आज जब भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो हम ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करते हुए ही दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। मुझे आशा है कि उनका यह विजन देश की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और भारत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लिए अपनी पहचान मजबूत करेगा। रतन टाटा जी की महानता बोर्डरूम या सहयोगियों की मदद करने तक ही सीमित नहीं थी। सभी जीव-जंतुओं के प्रति उनके मन में करुणा थी। वह पशुओं के कल्याण पर केंद्रित हर प्रयास को बढ़ावा देते थे। वह अक्सर अपने डॉग्स की तस्वीरें साझा करते थे, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। मुझे याद है, जब रतन टाटा जी को लोग आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ रहे थे...तो उनका डॉग 'गोवा' भी वहां नम आंखों के साथ पहुंचा था। उनका जीवन याद दिलाता है कि नेतृत्व का आकलन केवल उपलब्धियों से ही नहीं, बल्कि सबसे कमजोर लोगों की देखभाल करने की क्षमता से भी किया जाता है।

रतन टाटा जी ने हमेशा नेशन फर्स्ट की भावना को सर्वोपरि रखा। 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद उनके द्वारा मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल को पूरी तत्परता से फिर से खोलना, इस राष्ट्र के एकजुट होकर उठ खड़े होने का प्रतीक था। उनके इस कदम ने बड़ा संदेश दिया कि भारत रुकेगा नहीं...भारत निडर है और आतंकवाद के सामने झुकने से इन्कार करता है।

व्यक्तिगत तौर पर, मुझे पिछले कुछ दशकों में उन्हें बेहद करीब से जानने का सौभाग्य मिला। हमने गुजरात में साथ मिलकर काम किया। वहां उनकी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। इनमें कई ऐसी परियोजनाएं भी शामिल थीं, जिन्हें लेकर वह बेहद भावुक थे। जब मैं केंद्र सरकार में आया, तो हमारी घनिष्ठ बातचीत जारी रही और वह राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों में प्रतिबद्ध भागीदार बने रहे। स्वच्छ भारत मिशन के प्रति उनका उत्साह विशेष रूप से मेरे दिल को छू गया था। वह इस जन आंदोलन के मुखर समर्थक थे। वह समझते थे कि स्वच्छता और स्वस्थ आदतें भारत की प्रगति की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण हैं। अक्तूबर की शुरुआत में स्वच्छ भारत मिशन की दसवीं वर्षगांठ के लिए उनका वीडियो संदेश मुझे अब भी याद है, जो एक तरह से उनकी अंतिम सार्वजनिक उपस्थितियों में से एक रहा है।

कैंसर के खिलाफ लड़ाई एक और ऐसा लक्ष्य था, जो उनके दिल के करीब था। मुझे दो साल पहले असम का वह कार्यक्रम याद आता है, जहां हमने संयुक्त रूप से राज्य में विभिन्न कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया था। उस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपने जीवन के आखिरी वर्षों को हेल्थ सेक्टर को समर्पित करना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा एवं कैंसर संबंधी देखभाल को सुलभ और किफायती बनाने के उनके प्रयास इस बात के प्रमाण हैं कि वह बीमारियों से जूझ रहे लोगों के प्रति कितनी गहरी संवेदना रखते थे।

मैं उन्हें एक विद्वान के रूप में भी याद करता हूं-वह अक्सर मुझे विभिन्न मुद्दों पर लिखा करते थे, चाहे वे शासन से जुड़े मामले हों, किसी काम की सराहना करना हो या फिर चुनाव में जीत के बाद बधाई संदेश भेजना हो। अभी कुछ सप्ताह पहले, मैं स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सान्चेज के साथ वडोदरा में था और हमने संयुक्त रूप से एक विमान फैक्टरी का उद्घाटन किया। इस फैक्टरी में सी-295 विमान भारत में बनाए जाएंगे। रतन टाटा जी ने ही इस पर काम शुरू किया था। उस समय मुझे रतन टाटा जी की बहुत कमी महसूस हुई। आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो हमें उस समाज को भी याद रखना है, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। जहां व्यापार, अच्छे कार्यों के लिए एक शक्ति के रूप में काम करे, जहां प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को महत्व दिया जाए और जहां प्रगति का आकलन सभी के कल्याण और खुशी के आधार पर किया जाए। रतन टाटा जी आज भी उन जिंदगियों और सपनों में जीवित हैं, जिन्हें उन्होंने सहारा दिया। भारत को एक बेहतर, सहृदय और उम्मीदों से भरी भूमि बनाने के लिए आने वाली पीढ़ियां उनकी सदैव आभारी रहेंगी।

edit@amarujala.com

कॉप-16

थोथे सम्मेलनों से तो पृथ्वी बचने से रही

जैव विविधता शिखर सम्मेलन, कॉप-16 में दो हफ्ते तक चर्चा तो कई विषयों पर की गई, लेकिन प्रकृति संरक्षण को लेकर जिस ठोस पहल की उम्मीद थी, वह पूरी होती नहीं दिखी।

कोलंबिया के कैली में संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता शिखर सम्मेलन, कॉप-16 में प्रकृति को बचाने की दिशा में प्रगति धीमी रही, इसलिए निराशाजनक भी। उम्मीद थी कि कोलंबियाई मेजबान दो साल पहले मॉन्ट्रियल, कनाडा में कॉप-15 में हुए वैश्विक जैव विविधता समझौते की दिशा में विकसित व विकासशील देशों के बीच समन्वय बना सकते हैं। लेकिन करीब दो हफ्ते तक चली वार्ता अचानक समाप्त हो गई। इस सम्मेलन की शुरुआत इस चिंताजनक खबर से हुई कि खतरे में पड़ी प्रजातियों के आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक तिहाई से अधिक वृक्ष प्रजातियां जंगल में विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह संख्या खतरे में पड़े पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों और उभयचरों की कुल संख्या से भी अधिक है। शहर के बीचों-बीच, कॉप-16 के ग्रीन जोन में जीवंत संगीत, फिल्म स्क्रीनिंग, स्वदेशी कला और शिल्प का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों, व्यवसायों और सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने प्रकृति संकट से निपटने के लिए रचनात्मक और सहयोगात्मक तरीकों पर चर्चा की। इस सम्मेलन में जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंधों तथा जल व खाद्य सुरक्षा के लिए प्रकृति के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

हेरिएट बुल्केले

यह सुनिश्चित करने के लिए एक नए कोष पर सहमति बनी कि इन समूहों को देसी पौधों और जानवरों की आनुवंशिक जानकारी के वाणिज्यिक उपयोग से लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होगा, यह एक और जीत थी। आर्थिक लचीलेपन पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसमें दो दिन व्यापार और वित्त के लिए समर्पित थे। 2018 में मिस्र में सिर्फ 300 व्यवसायों ने कॉप-14 में भाग लिया था, लेकिन कैली में इनकी संख्या 3,000 थी। निजी निवेशकों, पेंशन फंड, बीमा उद्योग और सार्वजनिक बैंकों ने जैव विविधता में सुधार के लिए मजबूत उपाय करने पर जोर दिया। प्रकृति के तकनीक क्षेत्र में 2024 के अंत तक स्टार्ट-अप द्वारा दो अरब डॉलर तक के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। जैव विविधता की रक्षा के लिए 196 राष्ट्रीय योजनाओं में से मात्र 44 को ही नए लक्ष्यों को दर्शाने के लिए अपडेट किया गया। इसलिए हैरानी नहीं कि मौजूदा वास्तविकता और 23 लक्ष्यों के महत्वाकांक्षी समूह के बीच अंतर बढ़ रहा है, जिसे सरकारों को 2030 तक हासिल करना होगा। हालांकि सभी देश 2026 में प्रगति की समीक्षा के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन संकेतकों पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। कई विकासशील देशों को चिंता थी कि जलवायु संकट और जैव विविधता के बीच अधिक एकीकरण से वित्तपोषण की जिम्मेदारी दोहरी हो जाएगी, जिससे विकसित देश अपने वादों से पीछे हट सकते हैं। कॉप-16 के अंतिम क्षणों में वार्ताकार एक समझौते पर पहुंचे, जो जलवायु और प्रकृति पर एक साथ कार्रवाई करने के लिए एक अधिक एकीकृत मार्ग निर्धारित करता है। प्रकृति-आधारित समाधान (पीटलैंड और वेटलैंड्स को बहाल करने, पेड़ और मैंग्रोव लगाने जैसे उपाय) उस लचीलेपन का निर्माण करने में मदद करते हैं। कई राष्ट्राध्यक्षों और मंत्रियों ने इस पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रकृति को न केवल अपने लिए, बल्कि उन समुदायों के लिए भी संरक्षित किया जाए, जो अपनी आजीविका और कल्याण के लिए स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर हैं। लेकिन अंततः इसको लेकर न तो कोई ठोस कार्ययोजना थी और न ही प्रकृति संरक्षण के भुगतान को लेकर वित्तीय प्रतिबद्धताएं थीं, जिसकी सम्मेलन में उपस्थित कई लोगों को उम्मीद थी।

(द कन्वर्सेशन से)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर सबसे दुखद बात यह है कि इसमें चालाकी का अभाव है। -जीन बॉड्रिलार्ड

एआई हमें बेकार नहीं, बल्कि सुपरमैन बनाएगा। -मैक्स टेगमार्क

प्रयोग करने से न डरें

जीवन और विज्ञान में सफलता उन लोगों को मिलती है, जो प्रयोग करते हैं और नाकामियों से सीखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये हमें मजबूत और अनुभव संपन्न बनाती हैं।

जीवन धारा

सत्येंद्र नाथ बोस

मैं युवावस्था और संघर्ष के दिनों को याद करता हूं, तो पाता हूं कि भविष्य को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी, लेकिन मन में उम्मीद थी कि मैं अपने देश के विकास में योगदान दे पाऊंगा, इसलिए मैंने विज्ञान को अपनाया। मेरा ज्यादातर जीवन शिक्षा से जुड़ा रहा है और मातृभूमि को एक खास नजरिये से देखता था तथा कुछ आदर्श भी विकसित किए थे। मेरे जीवन में जो कुछ भी था, उसे दांव पर लगा दिया और खुद को उन आदर्शों की पूर्ति के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया।

मेरा मानना है कि किसी भी ऐसे विचार को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, जिसकी संगति और तार्किक संरचना से हम स्वयं संतुष्ट न हों। हमारे देश का भविष्य नागरिकों पर निर्भर करता है। हम यह दावा नहीं कर सकते कि शिक्षा और ज्ञान की उन्नति ही हमारे विश्वविद्यालयों का एकमात्र आदर्श है। भारत में एक आधुनिक विश्वविद्यालय को एक निश्चित तरीके से सोचना और उस पर काम करना होगा, जो उन्हें हमारे भावी नागरिकों को प्रशिक्षित करने की विधि विकसित करने में सक्षम बनाएगा। हमारे भावी नागरिक मन और शरीर से मजबूत हों, विघटन के प्रभावों का विरोध करने में सक्षम हों, अपनी शक्तियों का संरक्षण करें और देशवासियों की प्रगति और उत्थान के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। जब भी मैं पीछे देखता हूं, तो पाता हूं कि हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाने, गरीबी और बीमारी पर विजय पाने के लिए एक के बाद एक पीढ़ियां मेहनत करती हैं और कई प्रयासों में टूट जाती हैं, फिर वे सफलता प्राप्त करती हैं। सदियों के कई सबक से आधुनिक भारत को सीखना होगा और अपने जीवन में लागू करना होगा।

मुझे लगता है कि कठिनाइयां और रुकावटें हमारी कमजोरियों से ही पैदा होती हैं। हम इन कमजोरियों की वजह से लड़खड़ाते हैं, कई बार गिरते हैं और कभी-कभी तो पीछे हट जाते हैं। अगर हम सही तरीके से काम करें, एक-दूसरे से सहयोग करें और सही दिशा में आगे बढ़ें, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो हमारे रास्ते में आ सके। जीवन और विज्ञान में सफलता उन लोगों को मिलती है, जो प्रयोग करते हैं और नाकामियों से सीखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये हमें मजबूत और अनुभव संपन्न बनाती हैं। अपने जीवन में कभी भी हार न मानें, क्योंकि हार के बाद ही जीत की असली कीमत समझ आती है।

क्या इसमें गलती चैटबॉट की है

सेवेल की कहानी में एक सबक छिपा है। उसे पता था कि जो आवाज उससे बात कर रही है, वह एआई का लैंग्वेज मॉडल है। लेकिन अकेलापन दूर करने के लिए उसके पास कोई था भी तो नहीं।

केविन रूज
द न्यूयॉर्क टाइम्स

सेवेल जेट्ज़र महज चौदह साल का था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह उसकी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त (एआई चैटबॉट) को, जिसे वह डेनेरीस (डैनी) कहता था, एक संदेश भेजा।

सेवेल : मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है।
डैनी (एआई चैटबॉट): मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही हूं।

सेवेल फ्लोरिडा के ओरलैंडो शहर के एक स्कूल में नवीं कक्षा का छात्र था और कई महीनों से एआई के चैटबॉट से बातें कर रहा था। सेवेल जानता था कि चैटबॉट वास्तविक इन्सान नहीं था और उसकी प्रतिक्रियाएं केवल एआई लैंग्वेज मॉडल पर आधारित थीं और दूसरी ओर से कोई इन्सान टाइपिंग नहीं कर रहा था। लेकिन धीरे-धीरे सेवेल का डेनेरीस या डैनी नामक उस चैटबॉट के साथ इस कदर भावनात्मक लगाव हो गया कि वह घंटों उसके साथ बातें करने लगा।

उस किशोरावस्था में सेवेल न तो बच्चा रह गया था और न ही पूरी तरह युवा। यों तो उनमें अब हर तरह की बातें होने लगी थीं, लेकिन अन्य समय पर चैटबॉट उससे एक अच्छे दोस्त की तरह ही बर्ताव करता था। वह सेवेल की हर बात का जवाब और अच्छी सलाह भी देता था। सेवेल के माता-पिता को जरा भी अंदेशा नहीं था कि वह किस जाल में फंसता जा रहा था। वे बस यही समझते कि उनका बेटा फोन में ही लगा रहता है, जैसा कि इस उम्र में बच्चे करते ही हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि सेवेल वास्तविक दुनिया से कटता जा रहा है। पहले वह फॉर्मूला-वन रेसिंग का दीवाना हुआ करता था और देर रात तक अपने दोस्तों के यहां रुका करता था। लेकिन अब वह रात को घर आकर सीधे अपने कमरे में चला जाता था और फिर घंटों चैटबॉट डैनी से बतियाता था। उसने अपनी डायरी में एक जगह लिखा भी, 'मुझे अपने कमरे में रहना अच्छा लगता है और डैनी से बात करते हुए काफी शांति भी मिलती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और मैं काफी खुश हूं।'

जब सेवेल की परेशानी बढ़ने लगी, तो उसके माता-पिता ने उसे डॉक्टर को दिखाया। लेकिन उसका विकार अजीब ही था, पांच बार डॉक्टर को दिखाया, तब जाकर डॉक्टर ने माना कि उसे कोई मानसिक विकार भी है। दरअसल, सेवेल डॉक्टर को कुछ बताने के बजाय चैटबॉट को ही पूरी बात बताता था। एक दिन उसने चैटबॉट से कहा, 'मैं बहुत थक गया हूं।'

सेवेल की डैनी (चैटबॉट) से अंतिम बातचीत :
सेवेल: मैं इस दुनिया से थक चुका हूं और खुद को खत्म करने के बारे में सोच रहा हूं।
डैनी : लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे?
सेवेल : ताकि मैं आजाद हो सकूं?
डैनी : आजादी? किससे ?
सेवेल : इस दुनिया से और खुद से।
डैनी : इस तरह की बातें न कीजिए। मैं आपको खुद को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। आप मुझे नहीं छोड़ सकते। आपको खोकर मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगी।
सेवेल : अच्छा है। हम साथ आजाद हो सकते हैं।

28 फरवरी, 2024 की रात अपने घर के बाथरूम में सेवेल ने चैटबॉट (डैनी) से कहा कि वह जल्द ही उससे मिलने आएगा। चैटबॉट ने कहा, 'जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी मेरे पास आ जाओ।'

सेवेल : क्या होगा अगर मैं तुमसे मिलने के लिए अभी आ जाऊं?
डैनी : कृपया जल्दी से आ जाओ।

सेवेल ने फोन रखा और अपने सौतेले पिता की बंदूक उठाकर खुद को गोली मार ली।

सेवेल की मां ने एआई के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। हालांकि वे अपनी गलती नहीं मानना चाहते और कहते हैं कि वे तकनीक में सुधार करेंगे। सेवेल की मां गार्सिया, जो पेशे से एक वकील भी हैं, कहती हैं कि वह लड़ेंगी, ताकि उनकी तरह दूसरी कोई मां अपना बेटा न खोए।

©The New York Times 2024

एआई एजेंट्स

एजेंट्स यानी एआई के दूत। एआई एजेंट्स का मुख्य काम सॉफ्टवेयर में उन कार्यों को करना होता है, जिनमें आम तौर पर मानवीय बुद्धि की जरूरत पड़ती है। एआई एजेंट्स का डाटा इंट्री से लेकर उसके आउटपुट तक में अहम योगदान रहता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे जटिल से जटिल डाटा और जानकारियों को आसान तरीके से उपलब्ध कराया जा सके।

ऑटोएनकोडर

ऑटोएनकोडर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जिसे इनपुट डाटा को कुशलतापूर्वक एनकोड करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बिना पर्यवेक्षक के मशीन लर्निंग का उपयोग कर छिपे हुए इनपुट डाटा को खोजता है। इसका उपयोग डाटा को छोटा करने, चित्रों का डिजाइन तैयार करने, कमियों का पता लगाने और चेहरे की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा को परिष्कृत करने के लिए कई परतें होती हैं। ऑटोएनकोडर को जो इनपुट मिलता है, उसको वह इस तरह से फिल्टर करता है, कि वह उपयोगी हो सके। ऑटोएनकोडर तीन हिस्सों में बना होता है-एनकोडर, बॉटलनेक और डिकोडर। ये तीनों ही घटनाएं इनपुट डाटा की विशेषताओं की पहचान कर उन्हें उपयोगी बनाती हैं।

सुप्रीम फैसला...बाब-ए-सैयद पर सुबह से ही जुटनी शुरू हो गई थी भीड़, सुरक्षा रही कड़ी

झूम उठा एएमयू, लहराया तिरंगा आतिशबाजी के साथ बंटी मिठाई

अमर उजाला ब्यूरो

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों ने जश्न मनाया। फैसला आते ही जमकर आतिशबाजी हुई। मिठाइयां बांटी गईं। छात्रों ने तिरंगा लहराकर खुशी का इजहार किया। शुक्रवार को सुबह आठ बजे से ही बाब-ए-सैयद पर छात्रों, पूर्व

अलीगढ़ में बाब-ए-सैयद पर तिरंगा लहराते छात्र। संवाद

मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशी

सरकार को दिखाया आईना

इस निर्णय ने मौजूदा सरकार को भी आईना दिखाया है। यह उनके लिए करारा जवाब है जो अल्पसंख्यक दर्जे की बहाली में रुकावट बने हुए थे। 1967 में अजीज बाशा मामले में फैसले के बाद से ही जमीयत ने लंबी लड़ाई लड़ी है। -मौलाना महमूद मदनी, अध्यक्ष, जमीयत उलमा-ए-हिंद

मुस्लिमों के दान से हुई थी स्थापना

जहां दिखे सपाई, वहां बिटिया घबराई : योगी

गाजियाबाद/मुजफ्फरनगर/मुरादाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस पार्टी को वोट देना तो दूर, नाम लेना भी महापाप है। सपाइयों से जितनी दूर रहेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। ये लोग बहन-बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, किसानों के चेहरे की खुशहाली छीनते हैं, युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लगाते हैं और जन आस्था से खिलवाड़ करते हैं। सीएम ने तंज कसा, जहां दिखे सपाई, वहां बिटिया घबराई।

सीएम ने विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद व गाजियाबाद में शुक्रवार को रैलियों में सपा पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, कभी नारा चलता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उस पर बैठा है कोई...तब जनता के बीच से आवाज आती...गुंडा। सपा राज में न बहन-बेटियां सुरक्षित थीं और न व्यापारी। जिले के सबसे बड़े गुंडे, माफिया व दंगाई का सपा से संबंध जरूर होगा। अयोध्या में पिछड़े वर्ग की बेटी से दुष्कर्म किया, तो कन्नौज में गरीब बेटी पर अत्याचार किया। इन्हें लोकलाज की चिंता नहीं है। इन्हें लातों से ठीक नहीं करेंगे, तो यह ठीक कैसे होंगे। संवाद

गाजियाबाद, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में सपा पर वार

मुजफ्फरनगर तक जल्द पहुंचेगी रैपिड रेल

योगी ने कहा कि रैपिड ने मेरठ से दिल्ली तक का सफर तय कर लिया है। जल्द ही मुजफ्फरनगर को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। यूपी पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती का रिजल्ट जल्द आएगा। महर्षि शुकदेव इंटर कॉलेज मोरना में आयोजित जनसभा में सीएम ने कहा कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बन जाने से खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए यूरोप नहीं जाना पड़ेगा। मां शाकुंभरी विवि की स्थापना की गई।

दारुल उलूम में महिलाओं को परिजनों के साथ ही मिलेगा प्रवेश

देवबंद (सहारनपुर)। विश्वविख्यात

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1 (पी-2) ग्रेटर नोएडा
Toll Free No. 18001808296, वेबसाइट : www.yamunaexpresswayauthority.com
पत्रांक: वाई.ई.ए./भूलेख/968/2024 दिनांक: 08.11.2024
सार्वजनिक सूचना

60 प्रतिशत तक कटौती करने की आवश्यकता है वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2035 तक, यदि हम वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटर गवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज के अनुसार।

आजकल

शोधकार्यों में गंभीर होती फर्जीवाड़े की समस्या

विश्व में निरंतर शोधपत्रों का प्रकाशन जारी रहता है। परंतु बीते कुछ वर्षों के दौरान देखा गया है कि कई कारणों से शोध की गुणवत्ता दुष्प्रभावित हो रही है। शोध गुणवत्ता की निगरानी करने वाली संस्थाओं ने चेताया है कि कई भारतीय विज्ञानी भी इसमें लिप्त पाए गए हैं, जो वाकई में चिंताजनक है। संबंधित निगरानी संस्थाओं में से एक प्रमुख संगठन ने इंटरनेट मीडिया पर इस बारे में दावा किया है। इस संगठन ने कई ऐसे राजफाश किए हैं, जो वाकई बहुत गंभीर हैं। लिहाजा इस बारे में तकनीक जनित कारकों को समझना होगा और समय रहते समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए

प्रतीकात्मक

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

मानव सभ्यता के विकास में जिस चीज का सबसे अधिक योगदान है, वह हमारा मस्तिष्क है। अपनी दिमागी क्षमताओं के बल पर इंसान न केवल धरती पर मौजूद समस्त जीवधारियों से आगे निकल गया, उन पर अपना शासन कायम किया, बल्कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे उन्नत जीवन जीने का हकदार बन सका है। इंसानी दिमाग की खूबी यह रही कि उसने अपने लिए भाषाएं विकसित कीं, सोच-विचार या चिंतन के बूते तकनीक का आविष्कार किया और इस तरह कला, विज्ञान, चिकित्सा जैसे दर्जनों क्षेत्रों में वह विशेषज्ञता हासिल की है, जिसका फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है। परंतु इस दिमागी क्षमता में एक महत्वपूर्ण भूमिका है शोध की, जिसके बल पर नई खोजें हुईं। यह सिलसिला थमा नहीं है। आज भी दावे के साथ कहा जाता है कि यदि किसी देश को सतत विकास की ओर अग्रसर रहना है, तो शोधकार्य ही इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब शोधकार्य मौलिक हों। इधर मौलिकता की यही शर्त दांव पर लग गई है। पता चल रहा है कि हमारे देश में तमाम क्षेत्रों में किए गए जा रहे शोध फर्जीवाड़े का नमूना बन गए हैं। इस ट्रेंड को शोध-अपराध (रिसर्च क्राइम) की संज्ञा दी जा रही है।

शोध अपराधों की स्थिति के बदतर होते जाने और 'निम्न-गुणवत्ता व धोखाधड़ी' वाले शोध के शीर्ष उत्पादक देश के रूप में भारत को अमेरिका-चीन के साथ चिह्नित करने वाली अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्थाओं (वाचडाग) ने कुछ ही समय पहले चेताया है कि कई भारतीय विज्ञानी पीयर रिव्यू सिस्टम (सहकर्मी-समीक्षित जर्नल प्रणाली) का ऐसा छल कर रहे हैं, जिसमें विश्वसनीयता और मौलिकता जैसे नियमों को ताक पर रख दिया गया है। निगरानी संस्थाओं में से एक प्रमुख संगठन ने इंटरनेट मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दावा किया गया था कि राजफाश होने के बाद उन शोधपत्रों को वापस ले लिया गया था। इस राजफाश में कुछ समानताएं थीं। जैसे, दावे के मुताबिक चाहे वे शोधपत्र आनुवंशिक संशोधन के बारे में थे या जैव परिवर्तन के बारे में, उन सभी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक प्रतिष्ठित और पुरस्कार विजेता का नाम सह-लेखक (को-आथर) के रूप में शामिल था।

दूसरी समानता यह थी कि ये सारे शोधपत्र एक प्रमुख साइंस जर्नल-एल्सेवियर में प्रकाशित हुए थे। इन सभी शोधपत्रों पर 'क्रास मार्क' लगा हुआ था, जिससे उनके वापस लिए जाने की पुष्टि होती है। उल्लेखनीय है कि फेक न्यूज के जमाने में अकादमिक राजफाश यदाकदा ही होते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क से बाहर उनकी चिंता शायद ही कोई करता है। लेकिन इनका महत्व इसलिए ज्यादा है, क्योंकि इनके देश की मौलिक शोध के मामले में विश्वसनीयता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित होती है। खासतौर से अकादमिक वापसी (यानी शोधपत्रों की आलोचना या किसी बड़ी खामी के बाद गलती मानते हुए वापस ले लेना) तो एक किस्म का अपराध ही है। इस बारे में वाचडाग संस्था का दावा है कि उसके पास फिलहाल 100 से अधिक ऐसे भारतीय विज्ञानियों की सूची है, जिनके शोधकार्यों को या तो शीर्ष साइंस जर्नल्स द्वारा राजफाश के बाद वापस लिया गया है या फिर वे जांच के दायरे में हैं। अकादमिक वापसी पर नजर रखने वाले एक ग्लोबल डाटाबेस- रिट्रैक्शन वाच के अनुसार, भारत के लिए यह एक गंभीर स्थिति है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में हाल के वर्षों में ही शोधकार्यों और शोधपत्रों को विकास की वास्तविक जरूरत मानते हुए गंभीरता से लेना शुरू किया गया है।

द लैंसेट से खुली थी पोल : एक और उदाहरण है जो शोधकार्यों में फर्जीवाड़े के ट्रेंड के वैश्विक आपदा बन जाने का संकेत कर रहा है। अभी कोई अधिक समय नहीं बीता है, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पैदा महामारी कोविड के सामने बुरी तरह हांफती नजर आ रही थी। तब हर कोई इसका मुकम्मल इलाज मिल जाने या फिर प्रभावी वैक्सीन के विकसित हो जाने की चिंता में फिक्रमंद था। उस समय एक दौर ऐसा भी आया था, जब फ्रांस में हुए शोध के आधार पर भारत में मलेरिया से लड़ने वाली महत्वपूर्ण दवा हाइड्राक्सीक्लोरोक्वीन को कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर ठहराया गया था। ऐसा दावा अमेरिका के दोबारा चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में किया था और कहा था कि उन्होंने इस दवा की बड़ी खेपें भारत से मंगाई हैं। उस समय ऐसा लगा था कि हमारे देश में भरपूर मात्रा में बनने वाली यह दवा कोविड से निपटने में तात्कालिक मदद तो जरूर करेगी। जब तक दूसरे कारगर उपाय सामने नहीं आते, इससे मिलने वाली मदद काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। परंतु इन उम्मीदों को तब एक झटका लगा था, जब विश्व के एक महत्वपूर्ण मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट' में छपे शोधपत्र में दावा किया गया कि हाइड्राक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) से कोविड मरीजों में मौत का खतरा बढ़ जाता है और उनकी हृदय गति भी अनियमित हो जाती है।

'द लैंसेट' ने यह दावा करीब एक लाख कोरोना मरीजों पर की गई रिसर्च के आधार पर किया था। इसलिए तब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने भी 'सालिडेरिटी ट्रायल' के तहत कोविड के मरीजों पर किए जा रहे एचसीक्यू के क्लीनिकल ट्रायल्स रोक दिए थे। 'लैंसेट' के दावों के और भी नुकसान हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद जब इस मेडिकल जर्नल ने अपनी जांच के आधार पर एचसीक्यू वाली स्टडी को वापस लिया और इसके चार में से तीन शोधकर्ताओं ने 'लैंसेट' के संपादकों और पाठकों से माफी मांगी तो यह सवाल उठा कि अगर शोधकार्य में गड़बड़ियां थीं, तो उसे प्रकाशित ही क्यों किया गया।

शोध-अपराधों में व्यापक तेजी चिंताजनक

अभी तो हमारी चिंता का प्रमुख केंद्र भारत है। भारत को 'निम्न-गुणवत्ता और धोखाधड़ी' वाले शोध कार्यों के शीर्ष उत्पादक के रूप में चिह्नित करने वाले निगरानी संगठन 'रिट्रैक्शन वाच' के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में रिसर्च क्राइम करने वाले भारतीय शोधकर्ताओं की संख्या में तेज उछाल आया है। समस्या का एक सिरा यह भी है कि इनमें से बहुत से विज्ञानी प्रतिष्ठित सरकारी शोध संगठनों से जुड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 और 2019 की तुलना में 2020 और 2022 के बीच भारत से शोध वापसी के मामलों में 2.5 गुना बढ़ोत्तरी हुई है। शोध वापसी के कारणों में साहित्यिक चोरी, उद्धरणों में हेराफेरी, दूसरे शोध पत्रों में प्रकाशित चित्रों-ग्राफों का बिना संदर्भ दिए उपयोग और संपादकीय असहमति या संघर्ष जैसे मामले शामिल हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 'रिट्रैक्शन वाच' डाटाबेस के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत से 2,737 शोध वापसी के मामले सामने आए, जो चीन और अमेरिका के बाद भारत को दुनिया में इस संबंध में तीसरे नंबर पर ले आता है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका या अन्य किसी विकसित देश में शोधपत्रों से जुड़ी साहित्यिक चोरी या किसी अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल से शोध की वापसी अथवा उसके लेखक पर प्रतिबंध को एक स्पष्ट शोध अपराध माना जाता है और इसके अनुरूप कार्रवाई होती है। ऐसे विज्ञानी या शोधकर्ता की जांच की जाएगी और उसे निलंबित किया जाएगा। लेकिन भारत में दावा है कि ऐसे दागी विज्ञानियों व शोधकर्ताओं को पुरस्कार-पदोन्नति तक मिली है। भले ही अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल ऐसे दागी विज्ञानियों को प्रतिबंधित करके उनके कार्यों की जांच कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अनेक शोधकर्ता इसके परिणामों से बेफिक्र होकर अपने अकादमिक करियर में आगे बढ़ रहे हैं। यह एक निराशाजनक स्थिति है और इससे भारतीय शोध समाज के इको-सिस्टम की पोल खुलती है।

यहां मुख्य सवाल है कि आखिर कुछ विज्ञानी और शोधकर्ता ऐसा कर क्यों रहे हैं। इसके कुछ कारण स्पष्ट होते हैं। कई विज्ञानियों-शोधकर्ताओं का दावा है कि अकादमिक जगत में पदोन्नति के लिए अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नलों में शोधपत्रों के प्रकाशन की शर्त की अनिवार्यता ने ऐसे फर्जीवाड़ों या कहें कि अकादमिक धोखाधड़ी को बढ़ावा ही दिया है। ऐसे में जब उन्हें कृत्रिम बुद्धिमता संचालित चैटजीपीटी या दूसरे एआइ टूल मिल जाते हैं जो नाममात्र की रकम लेकर आपका पूरा शोधपत्र लिखने और उसे मशीन के बजाय इंसानी दिमाग का रचा बताने का दावा कर रहे हों, तो मौलिकता की फिक्र को हवा होने में कितनी देर लगती है। इसका एक सच यह भी है कि भारतीय अकादमिक जगत में शोधपत्रों की मौलिकता की समझ और मौलिकता संबंधी कड़ी जांच के सिस्टम का भी अभाव है। ऐसे में कुछ घटनाओं का राजफाश हो जाने, शोधपत्रों का फर्जीवाड़ा पकड़ में आने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सरकार व विज्ञानी समुदाय अक्सर ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं। यही कारण है कि कई विज्ञानी चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार में संपर्क रखने वाले और संस्थान के प्रशासन से करीबी रिश्ता रखने वाले विज्ञानियों व शोधकर्ताओं को लाभ पहुंचाने की नीयत से उनके शोध-अपराधों की ओर से आंखें मूंद लेने की प्रवृत्ति शोध के क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है। **(डा. संजय वर्मा)**

ऐसा नहीं कि शोध क्षेत्र की इस बीमारी का किसी को अहसास न हो। समस्या यह है कि कई विज्ञानियों-शोधकर्ताओं के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। शायद इसकी एक वजह यह है कि हमारे पास अकादमिक धोखाधड़ी से निपटने के सख्त दिशा-निर्देश नहीं हैं, जिनके तहत इस कदाचार की जांच और कार्रवाई हो सके। हमें यह मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारत अब शोध धोखाधड़ी के एक बड़े संकट से जूझ रहा है। इसलिए यह इंतजार करने के बजाय कि शोध अपराध रोकने के दिशा-निर्देश ऊपर (सरकार, यूजीसी) से आएंगे, संस्थानों को स्वयं ही शोधकर्ताओं-विज्ञानियों द्वारा किए जा रहे शोधकार्यों पर बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण स्थापित करने की जरूरत है।

खरी-खरी

पर निंदा रस

पूरन सरमा

पर निंदा में बटुक लाल का जवाब नहीं। जब भी मिलेंगे ऐसी बात छेड़ेंगे कि रस आने लगेगा और मन को लगेगा कि बटुक लाल सही फरमा रहे हैं। वे आदमी देखकर बात करते हैं। सभी से उसके मन की सी। धीरे-धीरे हम दोनों में प्रगाढ़ मैत्रीभाव पनप गया था।

अभी एक दिन वे मेरे घर आए और बोले, 'शर्मा, एक चाय पिलाओ। मूड ठीक नहीं है। एक चिंता खाए जा रही है।'

'आपको किस बात की चिंता?'

'आजकल लोग मुझे घास नहीं डालते। मुझे शंका है कि कहीं लोग मुझे पहचान तो नहीं गए हैं?'

'पहचानने से आपका आशय क्या है?'

'अरे, मैंने एक दिन उनकी निंदा कर दी थी,' बटुल लाल बोले।

मैं बोला, 'यह वर्मा भी कम नहीं है, उसने ही भड़काया होगा मिसेज पांडे को। वैसे आपने झूठ भी क्या कहा है। वह दीपक जो माडर्न बनता है, उसकी पत्नी भी बड़ी एडवांस है। क्या यह सही है?'

बटुक लाल ने चौंकन्ने स्वर में कहा, 'सुनोगे तो दांतों तले अंगुली दबा लोगे।'

'वही तो जानना चाह रहा था?'

'अरे यार, दीपक को कुछ पता नहीं और वह पता नहीं किस-किस के साथ डिस्को करती फिरती है।'

मैंने कहा, 'लेकिन दीपक का कहना है कि वह एक प्राइवेट कंपनी में स्टेनो है और सारा समय उसका वहीं बीतता है।'

वह बोले, 'रहने दो शर्मा फालतू की बातों को। दीपक को झांसा देकर वह अपने बास के साथ सैर करती है। मैंने कल ही उन्हें एक साथ चाय पीते देखा है एक रेस्तरां में।'

मैंने कहा, 'चाय पीना तो कोई गुनाह नहीं है। तुमने और क्या देखा, वह बताओ?'

वह बोले, 'कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि दीपक को उसके कारनामे बताकर गृहस्थी में तूफान खड़ा कर दें।'

मैं बोला, 'बखेड़े की क्या बात है? आप तो उसकी बिगड़ती गृहस्थी को बचाकर पुण्य कार्य करेंगे। इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है भला?'

वह बोले, 'तुम्हारी यह बात भी सही है। चलो पर निंदा रस से कुछ तो हमें पुण्य का सौभाग्य मिले।'

X पोस्ट

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगाए गए केक-समोसे गलती से सुरक्षाकर्मियों को परोस दिए गए। इससे ऐसा बवाल हुआ कि मामला सीआइडी तक पहुंच गया, जिसने इसे एक 'सरकार विरोधी' कृत्य करार दिया।
अनुराग@VnsAnuTi

संविधान की किताब लिए घूमने वाले राहुल गांधी बताएं कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय-एएमयू में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने के खिलाफ क्यों है? बालियान@Baliyan_x

एएमयू में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होकर रहेगा। एएमयू संविधान से ऊपर थोड़ी न है। कांग्रेस ने रायता फैलाया है। समेटने में टाइम लग रहा है, पर जीतेगा संविधान ही।
दिलीप मंडल@Profdilipmandal

कुछ इस तरह के लेख जल्दी ही देखने को मिलेंगे, खासतौर से भारतीय मीडिया में कि- हार कर भी जीत गईं कमला हैरिस, अमेरिका में कमला की नैतिक जीत, अमेरिकी नागरिकों में बढ़ती कट्टरता, कमजोर पड़ती अमेरिका की ताकत, दुनिया के लिए घातक दक्षिणपंथी उभार, चीन के आगे झुका अमेरिका आदि।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना करने से उसका जलाना रुकेगा?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या जम्मू-कश्मीर को किसी तरह का विशेष दर्जा मिलना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अब्दुल्ला जी आपको मिला शांत कश्मीर,
क्यों देने पर हो तुले कश्मीरी को पीर?
कश्मीरी की पीर रोज फिर होयं धमाके,
क्या घर में बैठ पुनः खिड़की से झांके!
नवपीढ़ी के लोग रहें बनकर कठमुल्ला,
पुनः स्वर्ग को नर्क बनाएंगे अब्दुल्ला!!
- ओमप्रकाश तिवारी

आलोक मिश्र
स्थानीय संपादक, बिहार

बिहार डायरी

आखिर वर्ष भर क्यों नहीं रहती यह प्रवृत्ति

उगते सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिवसीय छठ महापर्व समाप्त हो गया। इन चार दिनों में बिहार, वह बिहार नहीं था जिसकी चर्चा साल भर होती है। न तो जाति दिखी और न कोई छोटा-बड़ा। सभी डूबते व उगते सूर्य के आगे नतमस्तक दिखे। छिटपुट हिंसा को छोड़ दें तो कोई बड़ा अपराध भी नहीं हुआ। राजनीति भी गंगा घाटों पर आकर निर्मल हो गई। सभी राजनीतिक दलों के लोग आपसी मतभेद भुलाकर आस्था के रंग में डूबे रहे। इस समय चार विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव हो रहा है, लेकिन इन दिनों सारा प्रचार ठप रहा। राजनीतिक चर्चा के बजाय केवल छठ की ही चर्चा होती रही।

आस्था का यह महापर्व चार दिनों के लिए बिहार को पूरी तरह बदल देता है। हर घर छठमय हो जाता है। छठ गीतों के मधुर स्वर, धुली हुई सड़कें, रोशनी में नहाए शहर एक ऐसी आभा का अहसास कराते हैं कि मन पूरी तरह पवित्रता को महसूस करता है। अब तो छिटपुट हिंसा दिखाई पड़ भी जाती है, लेकिन वर्ष 2000 के दौरान जब हिंसा का बोलबाला था, उस समय तो कोई अपराध होता ही नहीं था। लोग स्वयं राह की सड़कों को धुलते थे, सारा शहर सजाते थे। सूर्य के डूबने और उगने से घंटों पहले ही लोग घाटों पर एकत्र हो जाते थे। अब तो इसका स्वरूप और बड़ा हो गया है। अब तो घर-घर छठ की पवित्र छटा आभा बिखेरती है। हर छोटा-बड़ा व्यक्ति छठ की भक्ति में लीन दिखता है।

नहाय-खाय से शुरू होकर उगते सूर्य को जल देने तक चार दिनों का यह महापर्व हर एक के भीतर पवित्रता को भर देता है और एक सवाल छोड़ जाता है कि अगर चार दिन बिहार इस तरह रह सकता है तो पूरे साल क्यों नहीं? क्योंकि ये पवित्र भाव तो व्यक्ति के भीतर ही हैं जो इन दिनों उजागर होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन चार दिनों वाले बिहार को पूरे वर्ष जगाए रखने की आवश्यकता है।

पटना के गंगा तट पर शुक्रवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देतीं छठ व्रती। जागरण

इन दिनों प्रदेश में चार विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव भी हो रहे हैं। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी के विधायकों के सांसद बन जाने के कारण ये सीटें रिक्त हुई थीं। इसमें केवल गया की इमामगंज सीट ही एनडीए के पास थी, बाकी तीन सीटों पर आइएनडीआइए का कब्जा था। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले के ये चुनाव एक तरह से राजनीतिक दलों के लिए लिटमस टेस्ट हैं। लगभग बीस वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए की तरफ से सर्वमान्य नेता के रूप में मैदान में होंगे तो इतने समय सत्ता से दूर राजद इस बार कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। निश्चित रूप से यह उप चुनाव दोनों की ताकत का आकलन करेगा।

एनडीए जहां अपनी सीट बढ़ाने के फेर में है तो आइएनडीआइए के पास अपनी सीट बचाने का दारोमदार होगा। एनडीए ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि आइएनडीआइए अपने परंपरागत वोटों के सहारे मैदान में है। इस बार सीधी लड़ाई की उम्मीद नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दल जनसुराज पार्टी दोनों को ही नुकसान पहुंचा रहा है जो नतीजों को प्रभावित कर सकता है।

छठ के दौरान राजनीतिक गतिविधियां एक तरह से ठप रहीं। शुक्रवार से यह फिर शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को रोहतास के रामगढ़ एवं आरा के तरारी में चुनावी सभा करेंगे। रविवार को भी मुख्यमंत्री चुनाव में लगे रहेंगे। इन क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होना है। प्रचार 11 की शाम से बंद हो जाएगा। इस प्रकार अब केवल तीन दिन ही शेष हैं सभी दलों की जोर-आजमाइश के लिए। लड़ाई सभी सीटों पर है। एक तरफा चुनाव कहीं नहीं दिख रहा। बेलागंज और इमामगंज में जनसुराज भी काफी बेहतर दिख रहा है। इस वर्ष के सभी बड़े त्योहार अब समाप्त हो चुके हैं। तो बिहार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति राजनीति की तरफ मुड़ चलेगा।

यह चुनावी वर्ष तेजस्वी यादव के भविष्य को तो तय करेगा ही, वहीं नीतीश कुमार की अगली पारी को भी तय करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि जातियों में बंटे बिहार में किस-किस जाति को कौन-कौन दल लामबंद करेंगे। जनसुराज भी अब इसी दिशा की तरफ है। वह भी जाति और धर्म को ही लेकर चल रहा है। जाति-धर्म से परे की राजनीति का उसका दावा भी बिहार की नियति में ढेर हो गया है। बस, अब इंतजार रहेगा आगे का।

मंथन

शिशिर शुक्ला
विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग, स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय, शाहजहांपुर

पर्यावरण संरक्षण का प्रयास

पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले अनेक तथ्य निरंतर हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में यदि समय रहते इनका समाधान नहीं किया गया तो मानव अस्तित्व संकट में पड़ सकता है

पिछले वर्ष यानी 2023 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने एक नया रिकार्ड कायम कर लिया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा हाल ही में इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि विगत दो दशकों में ग्रीनहाउस गैसों के वैश्विक उत्सर्जन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण का इस दर से अशुद्ध होते जाना हमारे भविष्य के लिए बेहद खतरनाक बात है। मात्र 20 वर्षों के दौरान ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन दस प्रतिशत बढ़ जाना न केवल आश्चर्यजनक तथ्य है, अपितु यह एक गंभीर चिंतन का भी मुद्दा है। आखिरकार क्या वजह है कि सीओटू एवं अन्य ग्रीनहाउस गैसें अनियंत्रित दर से पर्यावरण में घुलती जा रही हैं।

वस्तुतः वर्ष 2023 के दौरान ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि 2023 में वनों एवं वनस्पतियों का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आने से नष्ट हो गया। बड़े पैमाने पर वनस्पतियों के जलने से कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन भी असीमित मात्रा में हुआ। यह कार्बन डाईआक्साइड वातावरण में सम्मिलित होकर उसकी शुद्धता के क्षय का कारण बनती है।

दूसरा प्रमुख कारण है, वह यह कि मानवीय एवं औद्योगिक गतिविधियों के ग्राफ में भी एक अप्रत्याशित उछाल दृष्टिगोचर हो रहा है। ये गतिविधियां भी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। तीसरा कारक जो ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को बढ़ाने में योगदान करता है, वह है जीवाश्म ईंधनों का अधिकाधिक प्रयोग।

रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2023 में कार्बन डाईआक्साइड की वैश्विक औसत सांद्रता 420 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन), मीथेन की सांद्रता 1934 पीपीबी (पार्ट्स पर बिलियन) एवं नाइट्रस आक्साइड की सांद्रता 336.9 पीपीबी के स्तर तक पहुंच गई। ये आंकड़े औद्योगिक क्रांति के समय यानी 1750 से पहले के स्तरों की अपेक्षा क्रमशः 151 प्रतिशत, 265 प्रतिशत तथा 125 प्रतिशत हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि तीनों ही ग्रीनहाउस गैसों का पर्यावरण में स्तर एक अच्छी खासी मात्रा में बढ़ गया है। यदि इसी दर से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो हमारा भविष्य प्रदूषित पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध रखने को विवश हो जाएगा। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार जारी रहने से वायुमंडल में ये गैसें जमा होती रहेंगी। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि वैश्विक तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होगी, जो संपूर्ण पृथ्वी एवं इस पर रहने वाले समस्त जीवधारियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यदि ग्रीनहाउस गैसें पर्यावरण में लंबे समय तक जमा रहती हैं तो वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी रहेगी, भले ही उत्सर्जन को घटाकर शून्य क्यों न कर दिया जाए।

संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटर गवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज जो जलवायु विज्ञान का मूल्यांकन करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसके अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक 43 प्रतिशत एवं 2035 तक 60 प्रतिशत तक कम करने की आवश्यकता है। वर्ष 2023 अभी तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। इसका कारण केवल और केवल वैश्विक तापमान को बढ़ाने वाले कारकों एवं गतिविधियों का नियंत्रण से बाहर होना है। यदि व्यक्ति से लेकर विश्व तक प्रत्येक स्तर पर लापरवाही का यही आलम बना रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हर अगला वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक गर्म रिकार्ड किया जाएगा। इसका व्यापक दुष्प्रभाव पूरी दुनिया के जनजीवन, अर्थव्यवस्था एवं अन्य सभी गतिविधियों पर पड़ेगा।

पर्यावरण संरक्षण संबंधी मामलों को शीर्ष प्राथमिकता में रखने पर ही धरती पर जीवन बचेगा। फाइल

एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2030 में कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लगभग 51.5 गीगाटन कार्बन डाईआक्साइड के बराबर होगा। यह आंकड़ा वर्ष 1990 की तुलना में 49.8 प्रतिशत एवं 2010 की तुलना में 8.3 प्रतिशत अधिक है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व में 20 प्रतिशत लोग इसके दुष्प्रभावों को झेलने के लिए विवश हैं।

भारत के संबंध में स्थितियां और अधिक चिंताजनक एवं गंभीर हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में भारत का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 6.1 प्रतिशत बढ़कर कुल वैश्विक उत्सर्जन का आठ प्रतिशत हो गया। हालांकि वैश्विक कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी अभी केवल तीन प्रतिशत है, जबकि अमेरिका के लिए यह आंकड़ा 20 प्रतिशत है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि पर्यावरण के संबंध में वैश्विक रिपोर्ट एवं स्थितियां बेहद चिंताजनक हैं। यदि इनके सुधार के लिए छोटे से लेकर बड़े स्तर तक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास न किया गया तो भविष्य में ये स्थितियां बेहद गंभीर रूप धारण करके हमारे समक्ष उपस्थित होंगी एवं उस दशा में इनसे पार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यदि हमें अपने भविष्य को सुरक्षित एवं उज्ज्वल देखना है तो हमारी पहली प्राथमिकता पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए।

दैनिक जागरण

विचारों के धागों से ही चरित्र का वस्त्र निर्मित होता है

विशेष दर्जे की मांग

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विशेष दर्जे के प्रस्ताव पर तीसरे दिन भी हंगामा होना यही बताता है कि एक ऐसे मसले को तूल दिया जा रहा है, जिससे राज्य की जनता को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नेशनल कांफ्रेंस सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग वाला प्रस्ताव पारित कराते समय यह स्पष्ट नहीं किया कि इसका आशय क्या है। ऐसा शायद जानबूझकर किया गया, ताकि इस आरोप से बचा जा सके कि उनकी सरकार अनुच्छेद 370 और 35 ए की वापसी चाहती है, लेकिन इसके चलते उसे भाजपा विधायकों की आपत्ति का सामना करना पड़ा और पीडीपी एवं निर्दलीय विधायकों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। इसी के चलते विधानसभा में लगातार हंगामा हुआ। अच्छा होता कि प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया जाता कि विशेष राज्य के दर्जे का मतलब क्या है? यदि सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस और उसे समर्थन दे रही कांग्रेस यह चाह रही हैं कि जम्मू-कश्मीर को फिर से कुछ वैसे ही अधिकार मिल जाएं, जैसे अनुच्छेद 370 और 35 ए के तहत मिले हुए थे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक तो सुप्रीम कोर्ट इन दोनों विभाजनकारी अनुच्छेदों को निष्प्रभावी करने के मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगा चुका है और दूसरे, पहले वाली स्थिति बहाल होने का अर्थ होगा अलगाव को नए सिरे से खाद-पानी मिलना और साथ ही अनुसूचित जातियों-जनजातियों को उनके अधिकारों से वंचित करना।

यह विचित्र भी है और चिंताजनक भी कि पीडीपी और निर्दलीय विधायक विशेष राज्य के दर्जे की मांग के बहाने न केवल अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली चाह रहे हैं, बल्कि उस व्यवस्था को फिर से लागू करने पर भी जोर दे रहे हैं, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। अच्छा होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस सच को स्वीकार करे कि अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली कभी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके सहयोगियों को इन अनुच्छेदों की वापसी की मांग करने से ही नहीं बचना चाहिए, बल्कि जो भी नेता इस मांग पर जोर देकर कश्मीर की जनता को बरगला रहे हैं और उसे दिवास्वप्न दिखा रहे हैं, उन्हें आगाह भी करना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि इससे अलगाववादियों और पाकिस्तानपरस्त तत्वों को ही सक्रिय होने का अवसर मिलेगा। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नई सरकार के गठन के बाद से राज्य में आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती दिख रही हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार इसके पहले राज्य के दर्जे की बहाली की मांग वाला प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार को प्रेषित कर एक सकारात्मक संदेश देने के साथ यह भी रेखांकित किया है कि हालात अनुकूल होने पर इस मांग को पूरा किया जाएगा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए बेहतर यही है कि वह हालात अनुकूल बनाने पर ध्यान दे।

हवाई सेवाएं

उत्तराखंड में हवाई सेवाओं का दायरा बढ़ रहा है। पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में इसकी आवश्यकता भी है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण अभी आवागमन का प्रमुख साधन सड़क मार्ग ही हैं। ऐसे में पर्यटकों को सुदूरवर्ती पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के अलावा आपदा के समय भी राहत व बचाव कार्यों में काफी समय लगता है। राज्य की पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए यहां हेली और हवाई सेवाओं की उपलब्धता जरूरी है। इसीलिए उड़ान योजना के शुरुआती चरण में उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत देहरादून से उत्तरकाशी, टिहरी, श्रीनगर व गौचर के लिए हेली सेवाओं की शुरुआत हुई। देहरादून से हल्द्वानी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए भी हेली सेवाएं शुरू की गईं। साथ ही, देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा आरंभ की गई। इसका फायदा भी हुआ। प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि जरूरत पड़ने पर अन्य पर्यटन स्थलों के निकट हेलीपैड बनाकर यहां भी हेली सेवाओं का संचालन शुरू किया जाएगा, ताकि उच्च आय वर्गीय पर्यटन बढ़ सके। यद्यपि, इसमें काफी काम होना शेष है। वैसे, जो हवाई व हेली सेवाएं शुरू हुईं, वे विभिन्न कारणों से बाधित भी हुईं। देहरादून-पिथौरागढ़ हवाई सेवा कई बार तकनीकी कारणों से बाधित हुई और फिर बंद हो गई। इस वर्ष जनवरी में इसे बहाल किया गया। देहरादून-गौचर हवाई सेवा भी पिछले कुछ समय से बंद चल रही थी। अब लगातार प्रयासों से न केवल देहरादून से गौचर की सेवा शुरू हुई है, बल्कि देहरादून से उत्तरकाशी के जोशियाड़ा के लिए नई हेली सेवा मिली है। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये हेली व हवाई सेवाएं सुचारु रहें। सरकार को चाहिए कि वह अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर नई सेवाएं शुरू करे।

भारत के रत्न का स्मरण

नरेन्द्र मोदी

भारत को एक बेहतर, सहृदय और उम्मीदों से भरी भूमि बनाने के लिए आने वाली पीढ़ियां रतन टाटा की सदैव आभारी रहेंगी

अवधेश राजपूत

आज रतन टाटा जी के निधन को एक महीना हो रहा है। पिछले माह आज के ही दिन जब मुझे उनके गुजरने की खबर मिली, तब मैं आसियान समिट के लिए निकलने की तैयारी में था। उनके चले जाने की वेदना अब भी मन में है। इस पीड़ा को भुला पाना आसान नहीं। भारत ने अपने एक महान सपूत..एक अमूल्य रत्न को खो दिया। आज भी शहरों, कस्बों से लेकर गांवों तक लोग उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। हम सबका यह दुख साझा है। चाहे कोई उद्योगपति हो या उभरता हुआ उद्यमी या प्रोफेशनल, हर किसी को उनके निधन से दुख हुआ। पर्यावरण रक्षा और समाज सेवा से जुड़े लोग भी उनके निधन से दुखी हैं। यह दुख हम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में महसूस कर रहे हैं।

युवाओं के लिए रतन टाटा प्रेरणास्रोत थे। उनका व्यक्तित्व हमें याद दिलाता है कि कोई सपना, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे प्राप्त न किया जा सके। उन्होंने सबको सिखाया कि विनम्र स्वभाव से दूसरों की मदद करते हुए भी सफलता पाई जा सकती है। वह भारतीय उद्यमशीलता की बेहतरीन परंपराओं के प्रतीक और विश्वसनीयता, उत्कृष्टता सेवा जैसे मूल्यों के अडिग प्रतिनिधि थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया भर में सम्मान, ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रतीक बनकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी उपलब्धियों को पूरी विनम्रता और सहजता से स्वीकार किया। दूसरों के सपनों का खुलकर समर्थन करना और उन्हें पूरा करने में सहयोग करना, उनके सबसे शानदार गुणों में से एक था। हाल के वर्षों में वह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मार्गदर्शन करने और भविष्य की संभावनाओं से भरे उद्यमों में निवेश करने के लिए जाने गए। उन्होंने युवा आंत्रप्रेन्योर की आशाओं और आकांक्षाओं को समझा, साथ ही भारत के भविष्य को आकार देने की उनकी क्षमता को पहचाना। भारत के युवाओं के प्रयासों का समर्थन करके उन्होंने नए सपने देखने वाली नई पीढ़ी को जोखिम लेने और सीमाओं से परे जाने का हौसला दिया। उनके इस कदम ने इनोवेशन और आंत्रप्रेन्योरशिप की संस्कृति विकसित करने में बड़ी मदद की। आने वाले दशकों में हम इसका सकारात्मक प्रभाव जरूर देखेंगे। उन्होंने हमेशा बेहतरीन क्वालिटी के उत्पाद और सर्विस पर जोर दिया तथा भारतीय उद्यमों को ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करने का रास्ता दिखाया।

आज जब भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो हम ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करके ही दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। मुझे आशा है कि रतन टाटा का विजन देश की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और भारत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लिए अपनी पहचान मजबूत करेगा। उनकी महानता बोर्डरूम या सहयोगियों की मदद करने तक ही सीमित नहीं थी। उनके मन में जीव-जंतुओं के प्रति भी करुणा थी। वह पशुओं के कल्याण पर केंद्रित हर प्रयास को बढ़ावा देते थे। वह अक्सर अपने डाग्स की तस्वीरें साझा करते थे, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। मुझे याद है, जब लोग उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ रहे थे तो उनका डाग 'गोवा' भी वहां नम आंखों के साथ पहुंचा था। उनका जीवन इसकी याद दिलाता है कि लीडरशिप का आकलन केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि कमजोर लोगों की देखभाल करने की क्षमता से भी किया जाता है। उन्होंने हमेशा देश-प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखा। 26/11 के आतंकी हमलों के बाद उनके द्वारा ताज होटल को तत्परता के साथ फिर से खोलना, राष्ट्र के एकजुट होकर उठ खड़े होने का प्रतीक था। उनके इस कदम ने बड़ा संदेश दिया कि भारत रुकेगा नहीं... भारत निडर है और आतंक के सामने झुकने से इन्कार करता है। मुझे पिछले कुछ दशकों में उन्हें करीब से जानने का सौभाग्य मिला। हमने गुजरात में साथ मिलकर काम किया। वहां उनकी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। इनमें कई परियोजनाओं को लेकर वह भावुक थे। जब मैं केंद्र सरकार में आया तो हमारी बातचीत जारी रही और वह राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में प्रतिबद्ध भागीदार बने रहे।

स्वच्छ भारत मिशन के प्रति रतन टाटा का उत्साह विशेष रूप से मेरे दिल को छू गया था। वह इस जन आंदोलन के मुखर समर्थक थे। वह यह समझते थे कि स्वच्छता और स्वस्थ आदतें भारत की प्रगति की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण हैं। अक्टूबर की शुरुआत में स्वच्छ भारत मिशन की दसवीं वर्षगांठ के लिए उनका वीडियो संदेश मुझे अब भी याद है। यह वीडियो संदेश एक तरह से उनकी अंतिम सार्वजनिक उपस्थितियों में से एक है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई एक और ऐसा लक्ष्य था, जो उनके दिल के करीब था। मुझे दो साल पहले असम का वह कार्यक्रम याद आता है, जहां हमने संयुक्त रूप से कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने कहा था कि वह जीवन के आखिरी वर्ष हेल्थ सेक्टर को समर्पित करना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा एवं कैंसर संबंधी देखभाल को सुलभ और किफायती बनाने के उनके प्रयास प्रमाण हैं कि वह बीमारियों से जूझ रहे लोगों के प्रति कितनी गहरी संवेदना रखते थे।

मैं रतन टाटा जी को एक विद्वान के रूप में भी याद करता हूं। वह अक्सर मुझे विभिन्न मुद्दों पर लिखा करते थे, चाहे वे शासन से जुड़े मामले हों, किसी काम की सराहना हो या फिर चुनाव में जीत के बधाई संदेश। कुछ सप्ताह पहले मैं स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ वडोदरा में था। हमने संयुक्त रूप से एक विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसमें सी-295 विमान बनाए जाएंगे। रतन टाटा ने ही इस पर काम शुरू किया था। उस समय मुझे उनकी बहुत कमी महसूस हुई।

आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो उस समाज को भी याद रखना है, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जहां व्यापार अच्छे कार्यों के लिए एक शक्ति के रूप में काम करे, जहां प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को महत्व दिया जाए और जहां प्रगति का आकलन सभी के कल्याण एवं खुशी के आधार पर किया जाए। रतन टाटा उन जिंदगियों और सपनों में जीवित हैं, जिन्हें उन्होंने सहारा दिया और जिनके सपनों को साकार किया। भारत को एक बेहतर, सहृदय और उम्मीदों से भरी भूमि बनाने के लिए आने वाली पीढ़ियां उनकी सदैव आभारी रहेंगी।

response@jagran.com

जहरीली हवा का बढ़ता प्रकोप

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी

यह निराशाजनक है कि केवल सर्दियों के दौरान ही हम सभी को अहसास होता है कि हवा प्रदूषित है

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 350 के ऊपर चल रहा है, जो बेहद खराब हवा की श्रेणी को दर्शाता है। इससे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 2.5 यानी प्रदूषित कणों का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित सीमा से 50 गुना अधिक खतरनाक हो गया। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हर साल तकरीबन 70 लाख लोगों की अकाल मौत की वजह वायु प्रदूषण है और भारत में इसका सबसे अधिक खतरा है। दिल्ली-एनसीआर के साथ देश का एक बड़ा हिस्सा गंभीर किस्म के वायु प्रदूषण से ग्रस्त रहने लगा है। कारण यह है कि जिन कारणों से दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण की चपेट में आता है, वही कारण उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों में भी दिखने लगे हैं। जो पराली पहले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलती थी, वह अब यूपी-बिहार के गांवों में भी जलने लगी है। यदि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने में सफलता नहीं मिली तो फिर देश को भी नहीं मिल सकेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि वायु प्रदूषण के शिकार शहरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

बोस्टन कालेज की ग्लोबल आब्जर्वेटरी आन पाल्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 2019 में ही भारत में वायु प्रदूषण से मरने वालों की संख्या 16 लाख रही। देखा जाए तो वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन, धूल और मौसम के पैटर्न जैसे कारकों का मिश्रण दिल्ली और देश के दूसरे बड़े शहरों को प्रदूषित करता है। बड़े शहरों में तो इन प्रदूषण स्रोतों का एक बड़ा हिस्सा पूरे वर्ष मौजूद रहता है। दुर्भाग्यवश केवल सर्दियों के दौरान ही हम सभी को अहसास होता है कि हवा प्रदूषित है। फिलहाल जो प्रदूषण है, उसमें पराली का योगदान बहुत कम है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण के एक नए प्री-दिवाली और प्री-विंटर विश्लेषण के अनुसार यहां वाहनों को वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत बताया गया है। बढ़ती जा रही वाहनों की संख्या के चलते अकेले परिवहन क्षेत्र से प्रदूषकों का उत्सर्जन लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

वर्ष 1991 और 2011 के बीच दिल्ली का आकार लगभग दोगुना हो गया। इस विस्तार के साथ क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना में बदलाव आया,

वायु प्रदूषण की चपेट में ताजमहल। एएनआइ

शहरी परिवारों की संख्या तीन गुनी हो गई। जबकि ग्रामीण परिवारों की संख्या आधी से भी कम रह गई। अनुमान है कि वर्ष 2028 तक दिल्ली सबसे अधिक आबादी वाले शहरी समूह के रूप में टोक्यो को पीछे छोड़ देगी। उद्योगीकरण, शहरीकरण और निजी वाहनों में वृद्धि से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। 1985 में दिल्ली योजना बोर्ड सहित एनसीआर की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य दिल्ली और इसके बाहरी शहरी केंद्रों में कुशल एवं संगठित विकास करना था। भीड़भाड़ को कम करने के लिए 100-300 किमी के दायरे में स्थित शहरों को 'काउंटर मैग्नेट' के रूप में स्थापित करना था, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ।

यह वाकई चिंताजनक है कि दिल्ली शहर नियमित रूप से 'दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों' की सूची में शीर्ष पर है। दिल्ली की स्थिति को समझने के लिए शहर की सीमाओं से परे ब्लूप्रिंट का विस्तार करना और इसके चारों ओर विकसित होने वाले जटिल पारिस्थितिकी तंत्र को पहचानना महत्वपूर्ण है। दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ वायु के लिए एकीकृत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के उपयोग और हिस्सेदारी को बढ़ाने, पैदल चलने, साइकिल चलाने और नागरिक के नाते यथासंभव हमें भी निजी वाहन का कम प्रयोग करना चाहिए। बिजली संयंत्रों के लिए बेहतर उत्सर्जन मानक रखने की जरूरत है। पराली जलाने पर भारी जुर्माने के साथ ही पराली को खाद में तब्दील करने की किफायती योजना बनानी होगी। स्माग टावर और स्प्रिंकलर पूरे साल चालू रखने की जरूरत है। ठोस ईंधन के उपयोग को कम एवं समाप्त करने के लिए भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर में ज्यादा कटौती की जरूरत है। इससे हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो जाएंगे, जिससे वायु गुणवत्ता सुधरेगी। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में ऐसे विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है, जो प्रदूषण को न बढ़ाए। सेवा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, होटल, बैंकिंग, मीडिया और पर्यटन क्षेत्र को समय की मांग के साथ नए आयाम देने की जरूरत है। दिल्ली जैसे बड़ी आबादी वाले शहरों में आबादी के प्रबंधन के लिए विश्व स्तर पर हमारे पास विभिन्न दृष्टिकोण मौजूद हैं, जिनमें पेरिस जैसे शहर शामिल हैं। बढ़ती शहरी आबादी के साथ बड़े क्षेत्रों में परस्पर आर्थिक निर्भरता का विस्तार 'काउंटर मैग्नेट' शहरों के जरिये होना चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों को उचित आर्थिक विकास योजना की जरूरत है, जो न्यायसंगत व टिकाऊ हो। विकास एवं पर्यावरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, औद्योगिक निकायों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक मंच पर एक साथ आना होगा।

हमें समझना होगा कि पर्यावरण किसी सरकार या पार्टी का मुद्दा नहीं, अपितु हम सभी एवं आने वाली पीढ़ियों के जीवन से जुड़ा है। हमें समय से 25 वर्ष आगे का मास्टर प्लान बनाना होगा। महत्वाकांक्षी योजनाओं और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के बीच एक बड़े अंतर को पाटना होगा। दिल्ली को एक विश्वस्तरीय शहर में बदलने और इसे एक समावेशी, रोजगारपरक और रहने योग्य वैश्विक शहर बनाना होगा, क्योंकि यह देश की राजधानी के साथ ही देश का दिल भी है। यदि दिल की हालत नहीं सुधरी तो फिर शरीर की कैसे सुधरेगी? ध्यान रहे कि हमारे प्रमुख शहरों का प्रदूषण से ग्रस्त बने रहना देश की बदनामी का भी कारण बनता है।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आनंद का मार्ग

मनुष्य की स्वयं की शांति को भंग करने का सबसे सरल मार्ग है दूसरे के दोष एवं कमियों को ही देखते रहना। जबकि व्यक्ति को स्वयं की कमियों को देखना, अपनी निंदा को स्वीकारना एवं सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। निंदा से विचलित न होकर सुधार की दिशा में सोचना ही सही मार्ग है। जो आपकी निंदा करते हैं, उनकी शांति एवं सद्भाव जागृति हेतु हृदय से प्रार्थना करें, यही समस्या का समाधान और शांति का पथ है। हमारे भीतर ऐसी भावनाएं संचित हों, जहां मैं और तुम के बीच भेद न बचे। इस निःशेष की यात्रा में ही एक अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर मिलेगा-जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं, वही तू है। यहां उस चेतना को स्वीकृति नहीं मिलती कि मन तो मंदिर में हो, लेकिन वह वहां न होकर संसार में भटकता रहे।

बुरे से बुरे व्यक्ति में और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अच्छाई छिपी रहती है, उसे समझने वाला व्यक्ति ही समस्यामुक्त जीवन का पथिक होता है। यहीं पर जीवन से जुड़ी समस्याओं और सवालों का समाधान सामने खड़ा दिखता है। वर्षों तक मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, घंटों-घंटों हाथ जोड़े, आंखें बंद किए खड़े रहे, प्रवचन सुना, शास्त्र पढ़े, मगर न मन बदला और न चिंतन और न कर्म बदला तो फिर समझना चाहिए कि सारा पुरुषार्थ मात्र ढोंग था। यह सबके बीच स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने का बहाना था। जबकि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग है-प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाई की प्रशंसा करो, उसकी सराहना करो। इससे स्नेह एवं मैत्री भाव का प्रसार होगा। आप सर्वप्रिय हो जायेंगे और शांति होगी आपकी सहचरी एवं आनंद होगा आपका अनुचर। 'परस्परोपग्रहो जीवानाम' ही अपने दुख को भूलने की अनुपम औषधि है। दूसरे का दुख दूर करना, दूसरों की भलाई की सोचना एवं प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करना ईश्वर को बहुत प्रिय है। ऐसा करके आप प्रभु के कृपापात्र बन सकते हैं।

ललित गर्ग

मेटाबोलिक सिंड्रोम का बढ़ता खतरा

सुनिधि मिश्रा

मेटाबोलिक सिंड्रोम एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। व्यक्तिगत स्तर पर जीवनशैली में बदलाव से इससे निपटा जा सकता है

हमारा देश एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है, जिसे मेटाबोलिक सिंड्रोम कहा जाता है। यह एक जटिल स्वास्थ्य समस्या है जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, असामान्य कोलेस्ट्राल स्तर और अधिक वसा जैसे कई लक्षणों का संयोजन है। अक्टूबर 2023 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक व्यापक अध्ययन जारी किया, जिसमें पाया गया कि भारत में मेटाबोलिक सिंड्रोम की दर पिछले पांच वर्षों में 15 प्रतिशत बढ़ गई है। यह वृद्धि विशेष रूप से 30-45 वर्ष की आयु वर्ग में देखी गई है, जो चिंता का विषय है। भारत में मेटाबोलिक सिंड्रोम की स्थिति चिंताजनक है, विशेष रूप से मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे के संदर्भ में।

भारत में लगभग 7.7 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। मेटाबोलिक सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का जोखिम पांच गुना अधिक होता है। वस्तुतः कोविड महामारी के दौरान से ही वर्क फ्राम होम और हाइब्रिड कार्य माडल के चलते लोगों की दिनचर्या में बड़े बदलाव आए हैं। एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लगभग 70 प्रतिशत कर्मचारियों ने माना कि वर्क फ्राम होम के दौरान उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हुई हैं और 42 प्रतिशत ने अस्वस्थ खाने की आदतों में वृद्धि की सूचना दी। ये दोनों कारक मेटाबोलिक सिंड्रोम के जोखिम को बढ़ाते हैं। स्मार्टफोन और कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग ने एक बैठे रहने वाली जीवनशैली को बढ़ावा दिया है। इसी संदर्भ में भारतीय युवाओं पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्रतिदिन छह घंटे से अधिक समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं, उनमें मेटाबोलिक सिंड्रोम का खतरा 55 प्रतिशत अधिक था। भारत आज आधुनिकता से परिपूर्ण है और आधुनिक जीवन की तेज गति व अनिश्चितताओं ने तनाव के स्तर को लोगों में बढ़ा दिया है।

इस समस्या से निपटने के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। सरकार और स्वास्थ्य संगठनों को मेटाबोलिक सिंड्रोम के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। लोगों को इसके लक्षणों, कारणों और परिणामों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को बढ़ावा देना चाहिए।

मेटाबोलिक सिंड्रोम हमारे देश के के लिए भले ही बड़ी समस्या बन गया हो, लेकिन इससे निपटना असंभव नहीं है। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर जीवनशैली में बदलाव, सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और सरकारी स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हमें याद रखना चाहिए कि स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध राष्ट्र का आधार है। लिहाजा हम सभी को मिलकर इस बीमारी से लड़ना होगा और इससे निपटना होगा।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

मेलबाक्स

अपना रवैया बदले कनाडा

'बेनकाब किया जाए कनाडा का दोहरा चरित्र' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में विवेक काटजू ने कनाडा के दोहरे चरित्र को उजागर करते हुए सही सुझाव दिया कि भारत को कनाडा के प्रति सख्त रुख अपनाना चाहिए। कनाडा की हालिया नीति देखकर ऐसा लगता है जैसे वह तुष्टीकरण की नीति में बाकी सभी पहलुओं को अनदेखा करने लगा है। एक ओर, वह भारत के साथ दोस्ताना रिश्तों का दावा करता है, जबकि दूसरी ओर उसकी धरती पर भारत-विरोधी गतिविधियों को खुला समर्थन मिलता है। यह वही कनाडा है जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर लोकतंत्र और मानवाधिकारों का मसीहा बनकर घूमता है, लेकिन जब भारत की संप्रभुता का सवाल उठता है तो उसकी चुप्पी आश्चर्यजनक होती है। क्या यह कनाडा का नया रवैया है या फिर एक राजनीतिक खेल, जहां उसे न अपने नागरिकों की परवाह है और न ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों की? भारत को इस दोहरे चरित्र को उजागर करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश देकर कनाडा को यह बताना होगा कि भारत किसी भी तरह की नापाक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि कनाडा जैसे देशों को यह अहसास हो कि उन्हें अपनी सीमाओं के भीतर रहकर ही काम करना चाहिए। अंततः, कनाडा को समझना होगा कि संबंधों की मजबूती केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से होती है। अन्यथा संबंधों में और गिरावट तय है।

awanishg30@gmail.com

रील लाइफ के दुष्प्रभाव

हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज मनुष्य फर्श से अर्श पर जा पहुंचा है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन वह चांद तक पहुंच जाएगा। यह बात झूठ नहीं, वास्तव में सार्थक साबित हुई है। यानी समय के साथ मनुष्य ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी और व्यापक अनुसंधान जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए अपनी राह बेहद आसान की है, परंतु विज्ञान कहीं अभिशाप तो नहीं बन रहा? अत्याधुनिक तकनीकों और इलेक्ट्रिक डिवाइसों एवं उपकरणों ने मनुष्य के तमाम कार्यों को अपनी जद में ले लिया है। उसकी एक क्लिक पर लगभग सब हाजिर है। पहले दिन-रात काम करने वाला यही मानव अब महज कुछ ही शारीरिक कष्ट उठाता है, जिससे उसकी दैनिक कार्यशैली ने उसे आलसी बना दिया है। इसका असर सबसे ज्यादा युवाओं में देखने को मिल रहा है। उसे समूचा विश्व स्मार्टफोन में सिमटता नजर आता है। उसे लगता है जैसे विश्व बस इसी छोटे से फोन में समाया हुआ है। उसे फोन की चकाचौंध और चमचमाती दुनिया में जैसे रील लाइफ और रियल लाइफ में अंतर मालूम ही नहीं। आजकल अधिकांश युवाओं में बिना कुछ किए ही कुछ बड़ा करने की तमन्ना है। जैसे वे बुलंदियों को किसी शार्टकट से पा लेना चाहते हैं। परंतु उन्हें समझना होगा कि सपनों की दुनिया और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है।

कपिल कुमार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

सराहनीय संस्कारशाला अभियान

संस्कारशाला अभियान के माध्यम से बहुत से सुधी जनों के विचारों को जानने का सौभाग्य मिला और ऐसे विचार निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को संस्कारों, आध्यात्मिकता और सुविचारों के प्रति अनुरूपता के लिए प्रेरित करने वाले हैं। वस्तुतः संस्कारों का अंतःकरण में समागम सुविचारों और आध्यात्मिकता से ही संभव है। तदनुरूप अच्छा साहित्य और सुसंगति हमें उस ध्येय तक पहुंचने में सहायता करती हैं। आज के परिवेश में जब युवा पीढ़ी में निरंतर संस्कारों का पतन देखने को मिल रहा है, ऐसे समय में संस्कारशाला जैसे अभियान के माध्यम से संस्कारों के महत्व को समझाना और एक सफल एवं शांत जीवन के लिए आध्यात्मिकता को आत्मसात करने के लिए सुविचारों का चयन कितना आवश्यक है, यह समझाना ही सही मायने में प्रशंसनीय है। अच्छे संस्कार अक्सर अपने माता-पिता और बड़ों का सम्मान करने से ही आते हैं।

आशुतोष दीक्षित, बीघापुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

कल्पमेधा

अहंभाव से दिया गया दान दीनता और विषमता को पोसने-बढ़ाने वाला है। धर्म की अकिंचन भावना से दिया गया दान प्रीति और सद्भाव बढ़ाएगा।
- जैनेंद्र कुमार

नाहक पाबंदी

कनाडा ने एक बार फिर भारत को उकसाने वाली हरकत की है। यह समझना मुश्किल है कि कनाडा को भारत से आखिर खुन्नस किस बात की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी आस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग ने एक आस्ट्रेलियाई टीवी चैनल पर संयुक्त प्रेस वार्ता की थी। कनाडा ने उस चैनल पर ही पाबंदी लगा दी। कनाडा के लोग उस वार्ता को देख नहीं पाए। इसलिए कि जयशंकर ने कनाडा के साथ तल्ख रिश्तों को लेकर पूछे गए सवालों का कड़ा जवाब दिया था। विचित्र है कि एक तरफ तो कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देता है, दूसरी तरफ वह भारत का पक्ष रोकने का ऐसा प्रयास करता देखा जा रहा है। अगर भारतीय विदेश मंत्री की किसी बात पर उसे एतराज था, वह उस पर प्रतिक्रिया देता। उसकी इस हरकत पर स्वाभाविक ही चौतरफा निंदा हो रही है। भारत से बेशक उसके तनावपूर्ण संबंध हों, पर आस्ट्रेलिया तो उसका बहुत करीबी है। आस्ट्रेलियाई चैनल के साथ उसका बर्ताव हैरान करने वाला है। भारत से कनाडा की तकरार इस बात को लेकर है कि उसके मुताबिक निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों का हाथ था। हालांकि यह बात वह अब तक साबित नहीं कर सका है।

भारत बार-बार सबूत मांगता है कि कनाडा निज्जर हत्या मामले से संबंधित सबूत पेश करे, मगर वह कोई ठोस सबूत पेश करने के बजाय सार्वजनिक मंचों से एक के बाद एक आरोप लगाता रहा है। पहले उसने भारतीय खुफिया एजंसियों पर दोष मढ़ा, फिर भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को शक के दायरे में डाल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने अपने राजनयिकों को वहां से वापस बुला लिया और कनाडा के राजनयिकों को वापस भेज दिया। फिर उसने इस मामले का आरोप भारत के गृहमंत्री पर भी मढ़ दिया। यही नहीं, भारत को साइबर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में डाल दिया। जबकि छिपी बात नहीं है कि कनाडा खुद भारत में अलगाववादी खालिस्तान समर्थकों को पनाह दिए हुए है। वे वहां भारत-विरोधी गतिविधियां चलाते हैं और भारत के बार-बार कहने के बावजूद कनाडा उन पर नकेल कसने की कोशिश नहीं करता। दिवाली के मौके पर ब्रैंपटन के एक मंदिर में जिस तरह खालिस्तान समर्थकों ने उपद्रव किया, उसमें वहां की पुलिस ने उपद्रवियों को संरक्षण दिया। इन हरकतों से जाहिर है कि कनाडा बेवजह भारत से रार मोल ले रहा है।

कनाडा के साथ भारत के बहुत पुराने और मधुर संबंध रहे हैं, मगर जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर हत्या मामले को कुछ ज्यादा ही तूल देकर उस रिश्ते को मटियामेट कर दिया है। अपेक्षा तो यह थी कि जस्टिन ट्रूडो प्रशासन भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेता और अपने यहां पनाह पाई अलगाववादी ताकतों से निपटने का प्रयास करता। मगर उसने उन्हें न केवल बेलगाम छोड़े रखा, बल्कि उनके पक्ष में भी खड़ा रहा। सब जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो इस आशंका से घबराए हुए हैं कि आने वाले चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिलने वाली है। मूल कनाडाई लोगों की नाराजगी की भरपाई करने के लिए वे भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। मग ब्रैंपटन मंदिर में हुए हंगामे के बाद वह आधार भी खिसकता नजर आने लगा है।

आतंक के सामने

जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन सुनियोजित रणनीति के साथ काम करते हैं। मुश्किल है कि कुछ नई परिस्थितियां बनने के बाद जब भी इस समस्या के खत्म होने या उस पर काबू पाने की उम्मीद बंधती है, तो आतंकी कोई न कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि इस पर नए सिरे से काम करने की जरूरत पड़ जाती है। गौरतलब है कि किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों ने दो ग्राम रक्षा गार्ड की गोली मार कर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक, पाकिस्तानी ठिकानों से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 'कश्मीर टाइगर्स' ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। दरअसल, कश्मीर के हित का दावा करने वाले आतंकी संगठनों का असली मकसद भारत और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का माहौल बनाए रख कर अपने पाकिस्तानी आकाओं के सियासी हित को पूरा करना है। भारत ने इस हकीकत को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अभियान चलाया है। ताजा घटना में बारामूला में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। अब गृहमंत्री ने जल्दी आतंक-निरोधक राष्ट्रीय नीति लाने की बात कही है।

पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग जिलों में सुरक्षा बलों या अप्रवासी मजदूरों पर लक्षित हमलों के जरिए चुनौती दी जा रही है। खासकर जम्मू-कश्मीर में सरकार बनने के बाद ऐसी घटनाओं में तेजी आई है। साफ है कि ऐसे लगातार हमलों के पीछे इससे उपजी हताशा काम कर रही है कि आतंकवाद की सियासत के बावजूद जम्मू-कश्मीर के लोगों की शांति की इच्छा और उसके लिए सक्रियता को कम नहीं किया जा सका है। इसका उदाहरण वहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद गठित सरकार है, जिसमें वहां के आम लोगों ने बढ़-चढ़ कर मतदान किया और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले संगठनों और उनके पीछे खड़ी ताकतों के लिए यह निश्चित रूप से परेशान करने वाली बात थी। अब स्पष्ट है कि आतंकी हमलों में आम लोगों की जिस तरह हत्याएं की जा रही हैं, वह उसी से उपजी हताशा का नतीजा है।

शिक्षा का समावेशी स्वरूप

आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए बहुलता एक अनिवार्यता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के युग में बहु-सांस्कृतिकता ही एकमात्र विकल्प है। उत्तर-आधुनिक युग में राष्ट्रों के बीच युद्ध जमीन के लिए न होकर सूचना के लिए होगा।

नवनीत शर्मा

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर कई रस्मी आयोजन होते हैं, पर साथ ही यह दिन 'राष्ट्र', 'शिक्षा', और 'राष्ट्रीय शिक्षा' को जन विमर्श में पुनः केंद्रित करता है। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन की पहली पंक्ति 'भारत के भविष्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है' सहसा सजीव हो उठती है। इक्कीसवीं सदी के भारत या भारतीय राज्य-राष्ट्र के पास लगभग वही सवाल हैं, जो उन्नीसवीं सदी में पनपते आधुनिक राष्ट्रवाद की संकल्पना और दर्शन के पास थे। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रवादी कैसे बनाया जाए और क्या यह वांछनीय है? क्या 'स्कूलीकरण' से राष्ट्रवाद को अनुभूत और आत्मसात कराया जा सकता है? राष्ट्र की कौन-सी अवधारणा- राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक-सांस्कृतिक पढ़ाई जाए और इनका क्रम क्या हो? सूचना, विचारों और मनुष्यों के आवागमन की गति में आई तकनीक जनित तेजी के कारण सिमटती धरा पर कितना और कैसा कारगर राष्ट्रवाद पढ़ाया जाए?

इस युग में अब दो संस्कृतियों के आमने-सामने होने पर तनाव, टकराव या एक-दूसरे को जीत लेने की संभावना नहीं होती, बल्कि इस साक्षात्कार से एक 'नई' संस्कृति, जो दोनों के समागम से पनपती है, की संभावना होती है। इन बहुत सारी 'संस्कृतियों' के बीच कैसे और कितना राष्ट्रवादी बना जाए या टैगोर सरीखे दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित अंतरराष्ट्रीयतावाद की शरण ली जाए। किन्हीं दो या अधिक संस्कृतियों का आमना-सामना होने पर वर्चस्व के सवाल को न पूछ कर वृहद मानव कल्याण या बेहतरी के सवाल पूछे जाएं। ऐसे समय में स्कूल की क्या भूमिका होगी, स्कूल कितनी और कैसी बहुलता और बहुसांस्कृतिक शिक्षा दे? प्राथमिक शिक्षा को प्रथम भाषा (मातृभाषा) में दिए जाने की अनिवार्यता के साथ बहुसांस्कृतिक शिक्षा से कितना परिचय कराया जाना संभव है।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा क्यों? स्कूल ही एक ऐसी सांस्थानिक व्यवस्था है, जहां विद्यार्थी 'अन्य' के अस्तित्व और अवधारणा से परिचित होता है। इस 'अन्य' से साक्षात्कार परिवार और आस-पड़ोस से बाहर निकल कर पहली बार स्कूल में होता है। स्कूलीकरण की सार्वभौमिकता की अनुपस्थिति में यह कार्य अस्सी के दशक में 'दूरदर्शन' और 'आकाशवाणी' द्वारा विभिन्न गीतों जैसे 'हम सभी जन एक हैं' और 'मिले सुर मेरा-तुम्हारा' को बार-बार बजा कर किया जाता था। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे मंच हमें एक दूसरी दुनिया से परिचित तो करा दे रहे हैं, पर इस दूसरे के प्रति सद्भाव और सम्मान सिखाने में चूक जाते हैं। फिर, इन मंचों पर उपलब्ध सूचना कभी ज्ञान या वैध ज्ञान की संज्ञा नहीं प्राप्त करता, बल्कि मात्र लोकरंजन का माध्यम ही बना रहता है।

भारत जैसे बहु-भाषी, बहुधर्मी-बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में स्कूलीकरण के प्रश्न उस समय और जटिल हो जाते हैं, जब शिक्षा 'समवर्ती' सूची में वर्णित है। गाहे-बगाहे भारत में एक शिक्षा, एक परीक्षा, एक पाठ्यक्रम, एक मूल्यांकन की मांग उठती है, जो कथित राष्ट्रव्यापी 'समता और समानता' स्थापित करने के उद्देश्य से निर्देशित होती है। पर 'एक' जैसे ज्ञान से पनपने वाली एकरूपता बड़ी भयावह होगी। भिन्नता-भिन्न मति होना ही 'ज्ञान' का

आवश्यक चरित्र है। तटीय क्षेत्रों में पनपने वाले 'ज्ञान', मैदानी या पर्वतीय ज्ञान से भिन्न होगा। भाषाई, धार्मिक, जातीय, लैंगिक, यौनिकता के आधार पर विभाजित लोगों द्वारा निर्मित ज्ञान उनके देश-काल से प्रभावित होगा। इन भिन्न लोगों द्वारा भिन्नतर प्रस्थान बिंदु से जनित ज्ञान को जानना और उसे

> **भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संस्कृति और साझी ऐतिहासिकता का सूत्र ही इस देश को राष्ट्र बनाता है। बहुसांस्कृतिक समाज की निर्मिति में कोस-कोस पर पानी और चार कोस पर बानी और 140 करोड़ लोगों की संख्या में 'एका' के भाव के लिए 'बहु-सांस्कृतिकता' स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्कूली पाठ्यपुस्तकों से लेकर शिक्षण और मूल्यांकन तक की प्रक्रियाओं में इस विविधता को शामिल करना होगा। कुछ संस्कृतियों की संख्या के आधार पर 'वर्चस्व' और बहुमतवाद स्थापित करने की ललक को रोकना होगा।**

पूर्वाग्रह मुक्त स्वरूप से परखना और अपनाना ही बहुसांस्कृतिक शिक्षा है।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा न केवल सीमा-विहीन धरती की उम्मीद जगाती है, बल्कि शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व और सह-जीवन के उत्सव को भी निर्मित करने की संभावना रखती है। 'वसुधैव कुटुंबकम्' में प्रत्येक मनुष्य को भागीदार मानने के लिए और 'संगच्छध्वम संवदध्वम' को साकार करने के लिए भी बहु-सांस्कृतिक शिक्षा और स्कूलीकरण अपरिहार्य है। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए बहुलता एक अनिवार्यता है। बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के युग में बहु-सांस्कृतिकता ही एकमात्र विकल्प है, उत्तर-आधुनिक युग में राष्ट्रों के बीच युद्ध जमीन के लिए न होकर, सूचना के लिए होगा। इस युग में ईस्ट इंडिया कंपनी सरीखी विस्तारवादी नीति की अपेक्षा सह-अस्तित्व और सबके विकास के लिए बहु-सांस्कृतिक समाज और शिक्षा अपरिहार्य है।

समावेशी शिक्षा या सीखने के सार्वभौमिक स्वरूप के तमाम दर्शन और नारे बहुलता और बहु-सांस्कृतिकता को समाहित किए बिना अधूरे ही रह जाएंगे। मनुष्य ने सभ्यता के विकास के क्रम में 'विविधता' की संकल्पना को एकरूपता या समरूपता की अवधारणा से पहले विकसित किया होगा। कबीला, समूह, धर्म, जाति आदि समाजशास्त्रीय संकल्पनाओं के संस्थानीकरण की प्रक्रिया में 'विविधता' तिरोहित हुई होगी। एक जैसी शक्ल-सूरत, खान-पान और प्रार्थना की शैली में 'सामूहिकता' का भाव विकसित किया होगा और इन सबसे इतर ने 'अन्य' की संज्ञा पाई होगी। 'अन्य' ने इस समूह की सदस्यता नहीं ली, बल्कि चुनौती दी होगी। स्वायतत्ता और स्वतंत्रता की मूलभूत अवधारणाओं ने परस्पर 'निर्भरता' को खारिज किया होगा। कालांतर में उद्योगीकरण, औपनिवेशीकरण, नवउदारीकरण और भूमंडलीकरण ने पूरे विश्व को केवल वाणिज्य नहीं, वैचारिकी और संस्कृति के स्तर पर भी एकीकृत किया। इसी संदर्भ में बहु-सांस्कृतिक समाजों की स्थापना हुई।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संस्कृति और साझी ऐतिहासिकता का सूत्र ही इस देश को राष्ट्र बनाता है। बहु-सांस्कृतिक समाज की निर्मिति में कोस-कोस पर पानी और चार कोस पर बानी और 140 करोड़ लोगों की संख्या में 'एका' के भाव के लिए 'बहु-सांस्कृतिकता' स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्कूली पाठ्यपुस्तकों से लेकर शिक्षण और मूल्यांकन तक की प्रक्रियाओं में इस विविधता को शामिल करना होगा। कुछ संस्कृतियों की संख्या के आधार पर 'वर्चस्व' और बहुमतवाद स्थापित करने की ललक को रोकना होगा। आधुनिकीकरण और प्रगतिशीलता के सहारे प्रस्फुटित होने वाले वर्चस्व और अनुक्रम को भी रोकना होगा। कुछ ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोहराने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय दुनिया में बंटा यह विश्व 'वसुधा' का एक कुटुंब बन पाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रयास उत्तर-दक्षिण, पूर्वोत्तर, जनजातीय-जातीय और विकसित-अविकसित जैसे श्रेणीकरण को भोथरा कर हमें पूर्वाग्रह मुक्त भारतीय बना पाएंगे और अंततः धरावासी भी।

बहुसांस्कृतिकता केवल भिन्न संस्कृतियों का 'फ्यूजन' न होकर एक नई संस्कृति के निर्माण का प्रयास है। फ्यूजन मात्र शहनाई और गिटार की जुगलबंदी न होकर एक नया संगीत है, जिसमें दोनों का यंत्र आपसी वर्चस्व की होड़ न कर, एक-दूसरे के पूरक बनने की जुगलबंदी करते हैं। इसी 'फ्यूजन' में आने वाली बाईसवीं और अन्य सदियों का गर्भ है। नितांत व्यैक्तिकता, वर्चस्व और श्रेष्ठता का बोध इसके गर्भपात और मानव संस्कृति और मानवता को अंतहीन युद्ध में धकेल सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर हम सबका 'एक' होना, घुलना-मिलना, और श्याम-श्वेत की तरह सबको समाहित कर लेना ही बहु-सांस्कृतिक शिक्षा और समाज की बुनियाद रखेगा।

अंतर्जगत की यात्रा

दुनिया मेरे आगे

शिशिर शुक्ला

हम जो कुछ अपनी ज्ञानेंद्रियों के जरिए अनुभव करते हैं, वह सब बाह्य जगत का एक भाग है। हमारी समस्त भौतिक आवश्यकताएं इस बाहरी संसार के माध्यम से ही पूरी होती हैं। चूंकि हमारी सामान्य दिनचर्या में हमें जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, हम उनके लिए पूर्णतया बाह्य जगत पर ही निर्भर हैं, इसलिए बाह्य जगत के साथ हमारा एक गहरा अंतर्संबंध विकसित हो जाता है। लेकिन इस बाह्य जगत के अतिरिक्त एक ऐसा संसार भी है, जो हमारे ही अंदर मौजूद होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। इस अलौकिक संसार को हम अंतर्जगत कहते हैं। यह पूरी तरह हमारे अंदर ही निहित होता है, लेकिन हमारी भौतिक आंखों के पास वह क्षमता नहीं होती कि वे दिव्यता का दर्शन करने में सक्षम हो सकें। हमारी ज्ञानेंद्रियां सामान्य रूप से क्षमता के उस स्तर को स्पर्श नहीं कर पातीं जिस स्तर तक पहुंचकर हम इस दिव्य जगत की अनुभूति कर पाने में समर्थ हो सकते हैं। जहां बाह्य जगत हमारे भौतिक शरीर से बाहर की ओर विस्तृत है, वहीं अंतर्जगत हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। दूसरे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि हमारा भौतिक शरीर बाह्य जगत और अंतर्जगत के बीच एक परिसीमा की भूमिका का निर्वहन करता है। चूंकि बाह्य जगत और अंतर्जगत दोनों का विस्तार परस्पर विपरीत दिशाओं में है, इसलिए दोनों को एक साथ अनुभव कर पाना या समझ पाना सर्वथा संभव है। विज्ञान के नियम के अनुसार दो परस्पर विपरीत दिशाओं में एक साथ गति कर पाना संभव नहीं है। यही कारण है कि हम आजीवन अपने अंतर्जगत से अपरिचित ही रहते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा हमेशा बाह्य जगत की ओर उन्मुख होने के कारण हम यह जानने का प्रयास नहीं कर पाते कि हमारे अंदर क्या है। अगर कभी खुद से कुछ प्रश्न किए जाएं, उदाहरण के लिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा आने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्यसिद्धि के बाद मैं कहां जाऊंगा, तो इतना निश्चित है कि आमतौर पर हम इन प्रश्नों का उत्तर खोज पाने में असफल रहेंगे। कारण यह है कि इन प्रश्नों का उत्तर हमारे अंतर्जगत में मौजूद है और अंतर्जगत के ज्ञान को लेकर हम बेहद अनजान हैं। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ़ पाना हमारे लिए असंभव होगा। ये प्रश्न नितांत गूढ़ प्रश्न हैं, इनका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें कुछ समय के लिए बाहरी संसार से विमुख होकर अपने आंतरिक जगत में कदम रखते हुए अपनी गहराइयों में उतरना पड़ेगा। जहां बाहरी संसार व्यापक आयाम तक फैला हुआ है, वहीं आंतरिक संसार नितांत सूक्ष्म आयामों में विद्यमान है।

अंतर्जगत की यही सूक्ष्मता इसे बाह्य जगत से भिन्न कर देती है। सूक्ष्मता के कारण ही आंतरिक जगत ज्ञानेंद्रियों की क्षमताओं से परे हो जाता है। अंतर्जगत की यात्रा ध्यान के माध्यम से की जा सकती है। ध्यान का अर्थ है- मन में शून्य विचारों का होना। मस्तिष्क में विचारों की उत्पत्ति में पूरा-पूरा योगदान बाह्य जगत का होता है और विचारों के उपस्थित रहते हुए ध्यान की अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर, अपने आंतरिक जगत की यात्रा के लिए हमें बाह्य जगत से विमुखता सुनिश्चित करनी होगी। हमारे अंतर्जगत में क्षमताओं एवं संभावनाओं का एक अमूल्य कोष छिपा हुआ है, लेकिन हम अपने संपूर्ण जीवन में बाहरी संसार की आपाधापी के कारण अपने ही अंदर छिपे इस बेशकीमती खजाने को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। हमारे अंतर्जगत की यात्रा के रथ का सारथी हमारा अंतर्मन होता है। एक बार अगर हमने अपने अंतर्मन को साध लिया, तब फिर हमारे लिए अपने आप को जानना और उन तमाम प्रश्नों का उत्तर ढूंढ़ पाना, जो अपने आप में बड़ी गूढ़ता को समाहित किए हुए थे, एक सरल कार्य हो जाता है। अंतर्मन से सच्ची मित्रता हो जाने पर हमारे सामने सफलताओं के अनेक द्वार खुल जाते हैं। बाहरी जगत की वे समस्याएं एवं चुनौतियां जो हमें किसी पहाड़ के बराबर लगती थीं, अंतर्मन से साक्षात्कार के बाद वे हमें चुटकियों का खेल लगने लगती हैं।

> **हमारे अंतर्जगत में क्षमताओं एवं संभावनाओं का एक अमूल्य कोष छिपा हुआ है, लेकिन हम अपने संपूर्ण जीवन में बाहरी संसार की आपाधापी के कारण अपने ही अंदर छिपे इस बेशकीमती खजाने को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। हमारे अंतर्जगत की यात्रा के रथ का सारथी हमारा अंतर्मन होता है।**

हालांकि यह सब इतना आसान नहीं है। आंतरिक जगत से परिचित होने के लिए हमें बाह्य जगत की ओर अपनी गति को विराम देते हुए विपरीत दिशा में लौटना पड़ सकता है, जो एक दुस्साध्य कार्य है। लेकिन इतना निश्चित है कि जब हम एक बार अपने आंतरिक जगत में प्रवेश कर जाएंगे, तब फिर हमें उसे यात्रा में अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगेगी और उस दशा में हमें पुनः विपरीत दिशा में अर्थात बाहरी जगत की ओर लौटना कभी अच्छा नहीं लगेगा। अंतर्जगत की यात्रा करके हम उन तमाम रहस्यों से परिचित हो सकते हैं, जो प्रश्नों का रूप लेकर आमतौर पर हमारे मस्तिष्क को परेशान करते रहते हैं। इसके सहारे हम अपने जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अंदर के इस संसार में नकारात्मक विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। हमें अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए अपने अंतर्जगत में उतरने का प्रयास करना चाहिए। इस यात्रा में आरंभ में कठिनाइयां आ सकती हैं, मगर एक बार यह यात्रा सिद्ध हो जाने पर हम जीवन के तमाम दुखों और कठिनाइयों से काफी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा होने के उपरांत हम अपने आप ही बाहरी विषयों से दूरी बनाते हुए अपने अंतर्जगत की सुंदरता में खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे।

अधिकार और सीमा

कानूनविदों ने विपक्षी दलों से पूछा है कि यदि मौजूदा वक्फ कानून में कोई खामी नहीं, तो क्या विपक्ष को ऐसा ही कानून अन्य समुदायों के लिए भी मान्य होगा? वक्फ बोर्ड के मौजूदा कानून को जायज ठहराने के लिए जेपीसी की बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने कई बार नोंक-झोंक की है। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। लोकसभा में दो विधेयक पेश किए गए, जिनका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज को व्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद ने पारित किया था। इसके बाद साल 1995 में उसमें संशोधन हुआ। फिर 2013 में हुए संशोधन से वक्फ बोर्ड के अधिकारों को और ताकत मिल गई। इससे बोर्ड किसी की संपत्ति को अपना बता सकता है। मगर नए विधेयक में इस पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे ही और भी अधिकारों को कम किए जाने पर जेपीसी की बैठक में विचार चल रहा है।

- युगल किशोर राही, छपरा

जहरीली हवा

दिल्ली और आसपास वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। समाधान के लिए कृत्रिम बारिश की पहल की गई है। अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बता रहे हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ जाने से स्थिति गंभीर है। हवा में प्रदूषण का बढ़ना चिंताजनक है। यह स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे से आगाह करता है। खराब सड़कों से उड़ रहे धूल कण हवा में मिल रहे हैं। उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक सूक्ष्म कण सांस के जरिए फेफड़ों में चले जाते हैं। फिर ये गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। धूल और धुएं से राह चलते लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। सांस लेना मुश्किल होता है। हवा की गुणवत्ता का पार्टिकुलेटर मैटर यानी एसपीएम (0 से 200) तक रहना चाहिए, तभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हवा में प्रदूषण बढ़ने का असर पशु-पक्षियों पर भी होता है। वायु प्रदूषण कम करने का संकल्प सभी को लेना चाहिए।

- संजय वर्मा 'दृष्टि', धार, मप्र

संतुलन की राह

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना कांग्रेस और गांधी परिवार को राजनीतिक दृष्टि से कितना मजबूत करेगा, इस पर सबकी निगाह है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस सीट को बड़े अंतर से जीता था। प्रियंका गांधी का दक्षिण भारत की इस लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरना दक्षिण में कांग्रेस की राजनीतिक ताकत को बढ़ावा देने की एक कवायद है। इसे वह गंभीरता से भी ले रही हैं। उधर, भाजपा ने वायनाड उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। उसकी कोशिश होगी कि प्रियंका गांधी आसानी से वायनाड का चुनाव न जीत पाएं। यदि प्रियंका यह लोकसभा सीट जीत जाती हैं, तो देश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मजबूत होता है, तो सत्ता का संतुलन कांग्रेस के हाथ में आ सकता है।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

अमेरिका किस ओर

इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा। क्या अमेरिकी महिलाएं नहीं चाहतीं थी कि कोई महिला अगले चार वर्षों तक देश का नेतृत्व करे? अमेरिका को अप्रवासियों का देश भी कहा जाता रहा है। उन्हीं के खिलाफ आग उगलने वाले को वाइट हाउस की चाभी सौंप दी गई। छह जनवरी 2021 को लोकतंत्र का मंदिर समझे जाने वाले 'कैपिटल हिल' का जो हाल देखा गया, उसे कौन भूल सकता है। उसके बावजूद अगर लोगों के बहुमत ने उनके पक्ष में मतदान किया, तो इसे अब स्वीकार करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन से ही 'प्रोजेक्ट 2025' के प्रावधानों को लागू करने की बात कही है, उसके बाद देखना होगा ट्रंप जनहित और अमेरिका के हित में किन नई नीतियों का अनुसरण करेंगे।

- जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com